₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

फरवरी 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

बागी बने कुशवाहा !

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार
आपके लिए लेकर आया है

Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि
राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

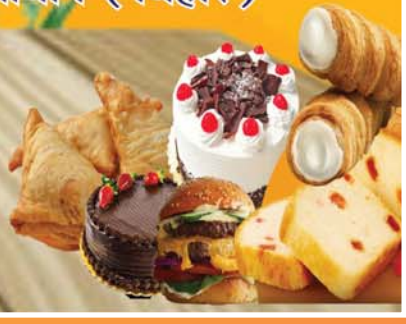

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

जैकी श्रॉप
01 फरवरी 1960

मनोज तिवारी
01 फरवरी 1971

ब्रह्मनंदम
01 फरवरी 1956

खुशवंत सिंह
02 फरवरी 1915

शमीता शेट्टी
02 फरवरी 1979

रघुराम राजन
03 फरवरी 1963

उर्मिला मांदोडकर
04 फरवरी 1974

अभिषेक बच्चन
05 फरवरी 1976

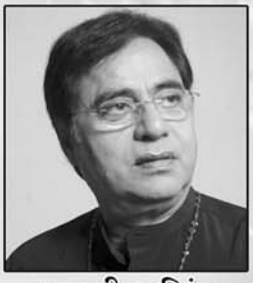

जगजीत सिंह
08 फरवरी 1941

मो० अजहरूद्दीन
08 फरवरी 1963

राहुल रॉय
09 फरवरी 1968

उदिता गोस्वामी
09 फरवरी 1984

कुमार विश्वास
10 फरवरी 1970

चौधरी अजीत सिंह
12 फरवरी 1939

स्व० सुषमा स्वराज
14 फरवरी 1952

टेकलाल महतो
15 फरवरी 1945

रणधीर कपूर
15 फरवरी 1947

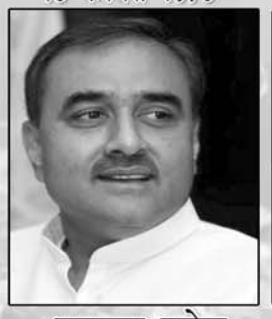

प्रफुल्ल पटेल
17 फरवरी 1957

स्व० जयललिता जयराम
24 फरवरी 1948

शाहीद कपूर
25 फरवरी 1981

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

हिन्दूराष्ट्र

बनाने निकले बागेश्वर धाम

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

सोसल मीडिया में हिन्दूराष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं तथा केन्द्र की मोदी सरकार ने पर्दे के पीछे रहते हुए लेकिन मध्यप्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी वाणी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर केन्द्रित कर लिया है। आप केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को जानते हैं और हो सकता है कि किसी स्टेट के विषय में भी जानकारी रखते हो लेकिन कोई मंदिर को भी सरकार के रूप में भी प्रसिद्धि है तो इस बात को सिद्ध किया है वर्तमान समय में (हिन्दूओं) सनातन धर्म के स्टार प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और उस सरकार का नाम है बागेश्वर धाम सरकार। यह धाम है संकटमोचन बाला (हनुमान जी) का जहां नारियल चढ़ाने एवं अर्जी लगाने की प्रथा है जहां पर तीन नारियल का रहस्य को समझने में विभिन्न धर्मा के गुरू, विभिन्न राजनीतिक दल के सूरमा, देश की मीडिया अपनी पूरी ताकत झोंक रही है की आखिरकार शास्त्री जी किसकी ठठरी को समझाने की कोशि कर रहे हैं। महज चंद वर्षो में यूं कहें कि 2021 के मध्य से बागेश्वर धाम ने पूरे विश्व में सनातन धर्म एवं हनुमान जी की महिमा की ऐसी गाथा लोगों तक अपने अनोखे अंदाज में पहुंचायी की विपक्षी दलो को लगने लगा की 2024 का मोदी का स्टार प्रचार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न बन जाये और भारत हिन्दूराष्ट्र। मोदी ने देश के बाहर तो भीतर शास्त्री ने सनातन का एहसास करा दिया है।

भारत देश धर्म प्रधान है और जब-जब धर्म पर प्रहार हुआ तब तब सनातन धर्म ने इसकी रक्षा की है और कोई न कोई संत ने बीड़ा उठाया है। विगत 10 वर्षों में भारत देश में सनातन धर्म का प्रचार बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। 2014 में जब केन्द्र सरकार (भारत देश) की कमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तो भारत का हिंदू के भीतर एक विश्वास जागृत हुआ की कोई है जो उनकी भावनाओं का कद्र करेगा। धारा 370 हटने के बाद तथा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण प्रारंभ होने के बाद सनातन प्रेमियों के भीतर जन जागरण हो गया है की कोई अब हिंदुओं को आंख नहीं दिखा पायेगा। सत्ता के लिए किस प्रकार धर्म की राजनीति होती आई है आजादी से लेकर आज तक लेकिन अब भगवा रंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और सोसल मीडिया के सक्रिय होने की वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सुर में जय श्री राम और जय हनुमान होने लगा है। आप बागेश्वर धाम की अर्जी घर बैठे हीं लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल पर रखना होगा और 'बगेश्वराय नमः' मंत्र के जाप करते रहें इसके लिए छतरपुर जिले जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अर्जी को बागेश्वर धाम ने स्वीकार कर लिया तो आप खुद पहुंच जाएंगे। 26 सितंबर से 04 अक्टूबर 2022 तक लंदन में अपनी प्रतिभा और बागेश्वर धाम की महिमा से विदेशी लोगों को भी हनुमानजी की कृपा से प्रभावित कर दिया धीरेंद्र शास्त्री ने। आज सोसल मीडिया के फायर ब्रांड के रूप में 10 से 90 वर्ष के लोगों के बीच छाए हुए हैं। हिन्दू नेता के रूप में भी धीरेंद्र शुक्ला उर्फ शास्त्री जी ने मीडिया को भी हैरत में डाल दिया है और सभी धर्मगुरु इसी जुगाड़ में हैं कि कैसे बागेश्वर धाम और शास्त्री जी की ख्याति को कलंकित किया जाए लेकिन शास्त्री जी ने ऐसी ठठरी बांध दी है कि कई लोगों ने हिन्दू धर्म में वापसी कर ली है। बागेश्वर धाम के निर्माण के स्पष्ट साल तो नहीं कोई साबित कर पा रहा है परन्तु बल बुद्धि के प्रतीक शिव के 11वें अवतार हनुमान जी की लीला वर्तमान समय में सुर्खियों में है। भारत तो भारत अब विदेशों में भी शास्त्री जी के फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और महज 26 वर्षीय शास्त्री जी ने देश को हिन्दुराष्ट्र बनाने का बिगूल फूंक दिया है जिसकी वजह से यह टारगेट पर हैं। हमेशा हनुमान जी की तरह तनावमुक्त रहते हैं और सबकी मन की बात पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1986-87 में बागेश्वर मंदिर को रेनोवेशन हुआ और बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज जिनको भगवान दास के रूप में भी पहचान था लेकिन सोसल मीडिया का प्रभाव नहीं रहने के कारण वह लोकप्रियता नही मिली जिसको धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आज पहुंचा दिया है। 1989 में बागेश्वर धाम गड़ा गाँव में विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ था और इसी परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्री जी ने पहुंचा दिया है और इनकी कथाशैली और हिंदुत्व की ललकार की वजह से यह आज हिन्दू के फायर ब्रांड हिन्दू संत नेता भी बन चुके हैं। पूरे देश में नंबर एक के कथावाचक एवं किसी के मन की बात का जानने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी आज लोकतंत्र के सभी स्तम्भ के बीच प्रधानमंत्री तक भी सार्वजनिक हो रही है और शास्त्री भी भक्तों की भावना को देखते हुए यह आह्वाहन कर रहे हैं कि **''तुम मेरा साथ दो-हम तुमको हिन्दुराष्ट्र देंगे''**। आजादी के वक्त आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीयों से अपील किया था ''तुम मुझे खून दो, हम तुम्हे आजादी देंगे''। दोनों कालखंड की कहानी में सामंजस्य है परन्तु अभी हिन्दू हीं जाति के नाम पर अलग अलग विचारधारा रखते हैं। पुरे कथाओं में भगवान शिव के बाघ रूप धारण करने वाले इस स्थान को व्याघ्रेश्वर तथा बागीश्वर से कालान्तर में बागेश्वर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सन् 1602 में राजा लक्ष्मी चन्द ने बागनाथ के वर्तमान मुख्य मन्दिर एवं मन्दिर समूह का पुनर्निर्माण कर इसके वर्तमान रूप को अक्षुण्ण रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत का धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया में खास स्थान रखने वाला मध्य प्रदेश का छत्तरपुर जिला पिछले एक वर्ष में राजनीति की कूटनीति से कहीं अधिक बागेश्वर धाम सरकार और उनके पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ धीरेंद्र शुक्ला चर्चा में हैं और श्री शास्त्री के यहां लगने वाले अर्जी की लोकप्रियता का बाजार गर्म है। आप बागेश्वर धाम की अर्जी घर बैठे हीं लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल पर रखना होगा और 'बगेश्वराय नमः' मंत्र के जाप करते रहें। इसके लिए छतरपुर जिले जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अर्जी को बागेश्वर धाम ने स्वीकार कर लिया तो आप खुद पहुंच जाएंगे। 26 सितंबर से 04 अक्टूबर 2022 तक लंदन में अपनी और बागेश्वर धाम की महिमा से विदेशी लोगों को भी हनुमानजी की कृपा से प्रभावित कर दिया धीरेंद्र शास्त्री ने। हिन्दू जागरण में कामयाब होते दिख रहे हैं शास्त्री जी।

जनवरी 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जातिगत जनगणना

ब्रजेश जी,

जनवरी 2023 अंक में केवल सच पत्रिका ने बिहार प्रांत में हो रहे जातिगत जनगणना पर पत्रकार अमित कुमार की आवरण कथा जातिगत जनगणना ओबीसी पर दलीय राजनीति! में प्रदेश में सत्ता के लिए इस प्रयास का सटीक समीक्षा की है। बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत जनगणना कराकर नीतीश कुमार केंद्र सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण से परास्त करने का प्रयास चल रहा है। सभी बिंदुओं को कलमबद्ध करने की सार्थक कोशिश की गई है।

✦ **मनोहर लाल, राजेंद्र नगर, पटना**

मालवीय सम्मान

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका द्वारा आयोजित मदन मोहन मालवीय केवल सच सम्मान 2022 की खबर को जनवरी 2023 अंक में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख सहित पत्रकारिता जगत के नामचीन संजय दुवेदी के साथ मदन मोहन मालवीय मिशन के अध्यक्ष श्री हरि शंकर सिंह के उदगार पढ़कर सही जानकारी प्राप्त हुई। केवल सच पत्रिका सम्मानित करके सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

✦ **किशोर जायसवाल, द्वारका 12, नई दिल्ली**

राम पर राजनीति

मिश्रा जी,

मै केवल सच पत्रिका का संपादकीय का नियमित पाठक हूं और कई बार पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर आप किसको टारगेट करके खबर लिख रहे हैं। बहुत ही सरलता से सच को सामने लाते हैं। जनवरी 2023 अंक में प्रकाशित संपादकीय राम रामायण पर राजनीति में पूर्ण बेबाकी के साथ बिहार के शिक्षामंत्री के बयान और रामायण की ढोल गवार.... की बात को बहुत हीं गंभीरता के साथ लिखकर जनता को सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दोनो पक्षों की बातों को प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ लिखा गया संपादकीय पठनीय और संग्रहणीय है।

✦ **महेंद्र यादव, खगौल बाजार, पटना**

शिखंडी

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका के जनवरी 2023 अंक में शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त निकले शिखंडी में आयोग के क्रिया कलाप पर कटाक्षपूर्ण तथा तथ्यों के साथ चुनौतीपूर्ण समीक्षात्मक बातों को गंभीरता पूर्वक पाठकों सहित सरकार तक पहुंचाने का जोखिम भरा आलेख लिखा है। चुनाव आयोग के आयुक्त को शिखंडी लिखना वास्तव में साहसिक पत्रकारिता का परिचय देता है। नरक विकास में नरक निगम और तीसरी खबर घोटाले के बादशाह निकला बिहार खनन विभाग की खबरें पत्रकारिता जिंदा है का सबूत केवल सच दे रहा है।

✦ **गजेंद्र सिंह, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर**

राजनीतिक समीक्षा

ब्रजेश जी,

सागर उपाध्याय ने जनवरी 2023 अंक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा पर राजनीतिक समीक्षा की है, जिसमे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दोबारा संजय जयसवाल पर मुहर लगने की बात को भी रखा है। सच में वर्तमान समय में संजय जयसवाल की जगह कौन लेगा पर विचार करने में संगठन भी धर्मसंकट में दिखती है। इस अंक में राजनीति की कई खबरों में सटीक और उपयोगी जानकारी के साथ साथ भ्रष्टाचार की प्रमुख खबरों को भी उचित स्थान दिया गया है। साक्षात्कार भी इस अंक में पढ़ने को मिला। संपादकीय भी इस अंक का बेजोड़ और मुंहतोड़ है।

✦ **मनोज उरांव, करमटोली चौक, रांची**

सेना का जज्बा

मिश्रा जी,

केवल सच पत्रिका के रक्षा क्षेत्र के स्तंभकार ललन सिंह की खबर सेना का जज्बा में जी 20 सम्मेलन के विषय में बेहतरीन जानकारी अपने आलेख के माध्यम से दी है। विश्व के कई महत्वपूर्ण देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पूरी आस्था और भरोसा जताया है की जी 20 सम्मेलन में समस्या के समाधान पर उम्मीद है। भारत के विदेशमंत्री जयशंकर के सार्थक प्रयास के साथ-साथ राष्ट्रपति के एक संदेश में यह कहा गया है कि 25 वर्ष में भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा होगा। सेना का सम्मान मोदी की सरकार में बढ़ा है इसको पूरा देश स्वीकार करता है।

✦ **रोहन रस्तोगी, बाबू बाजार, कोलकाता**

अन्दर के पन्नों में

समाजवाद की अंतिम यात्रा.....23

सीता का निर्वासन स्थल.....53

80

बेरहमी से मारपीट का आरोप.....94

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 17,	अंक:- 201,	माह:- फरवरी 2023,	मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

ललन कुमार प्रसाद 9334107607

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

उपसंपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

कुमार सौरभ 7004381748, 9102366629

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 09852168763

(म०):-

(ग्रा०) :-

बाढ़ :-

भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547

बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506

:-

गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :-

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543

नालन्दा :-

:-

नवादा :- अमित कुमार 9934706928

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406

:-

खगड़िया :-

समस्तीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

वैशाली :-

:-

छपरा :-

सिवान :-

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :- .

:-

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649

बगहा :-

मोतिहारी :-

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141

:-

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपौल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570

नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी
मो०- 6203723995, 9431073769

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636-9631490205

उप संपादक सह प्रदेश प्रभारी

अजय कुमार 6203723995-8409103023

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

संयुक्त संपादक

.....
.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

.....
.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	9431732481
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
मो०- 9431073769, 9955077308

☞ .e-mail:- kewalsach@gmail.com, ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी
" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
कुणाल कुमार सिंह	9988447877, 9472213899

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा कुमार	9608084774, 9835829947

हिस्सेदारी की मांग से बागी बने कुशवाहा

पुनः जदयू में वर्चस्व की जंग

प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सुर्खियों में छाये रहने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर वाकई में हर घड़ी विवादों से उलझा रहा है। एक तरफ शराबबंदी जैसे कठिन फैसले पर गंभीरता से चट्टान की तरह खड़े होकर बिहार को विकास का आयाम जोड़ने में प्रदेश के जिले भर में समाधान यात्रा का अलख जगा रहे हैं तो वही उन्ही की पार्टी में एक बार पुनः वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के कभी करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह की बगावत ने उन्हें परेशानी में डाला था और अब पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद् के सदस्य और नीतीश कुमार के पुराने मित्रों में सबसे करीबी उपेन्द्र कुशवाहा की बगावत ने उन्हें परेशानी में डाल रखा है। हालांकि बार-बार पार्टी के भीतर अगर वरीय नेताओं की बगावत सामने आते दिख रही है तो इसका भी बड़ा कारण ही होगा? एक दशक पहले तक भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय के साथ रहे नीतीश को वर्ष 2013 से मोदी नाम का जिन्न परेशान करने लगा, इस बाबत कभी साथ रहे तो कभी जुदा हुए। विडम्बना है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाह में मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को अपना उतराधिकारी मान उनके चेहरे पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जैसे बयान देकर जदयू के भीतर के नेताओं में भविष्य के आइने देखने को मजबूर कर दिया है। कई नेता मन ही मन सीएम के इस फैसले को मानने से इंकार कर रहे हैं तो कई ने अपनी बगावती तेवर सामने ही रख दी है। उनमें उपेन्द्र कुशवाहा का नाम पहला है, जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर बागी हो गये हैं। ऐसे में उपेन्द्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य कहां होगा, यह देखना है किन्तु कयास लगाये जा रहे हैं कि पुनः एक बार भाजपा में शामिल हो सकते हैं या फिर जदयू के नेताओं को तोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं! फिलहाल कुशवाहा जदयू को कमजोर होने की बात और राजद से डील जैसे सवालों को लेकर 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाई है और बैठक में कौन और कितनी संख्या में जदयू के नेता पहुंचते हैं, उसी से अनुमान लगेगा कि आगे कुशवाहा का नेक्सट स्टेप क्या होगा? नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के बीच उपेन्द्र कुशवाहा की हिस्सेदारी की मांग के विवाद पर प्रस्तुत है पत्रिका के संयुक्त संपादक अमित कुमार की विश्लेषनात्मक रिपोर्ट :-

बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा तेजी से चल रही है। बीते कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। ऐसे में जब बीते दिनों उपेन्द्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रुटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए तो उनसे मुलाकात के लिए बिहार बीजेपी के कई नेता पहुंचे। जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई और सोशल मीडिया पर तमाम अटकलों के साथ जंगल की आग की तरह फैल गई। बिहार की सियासत में यह सब अटकलें यूं ही नहीं शुरू हुईं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मिलने वाले संकेतों और पूर्व में उनके 'पाला बदल' के इतिहास को देखते हुए लगाई जाने लगीं। दरअसल, उपेंद्र की नाराजगी की खबरें तो तभी से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी की कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा, जिससे उपेंद्र कुशवाहा के अरमानों पर पानी फिर गया। अब अटकलों के बाजार में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से विदा लेने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लोगों के साथ उनकी तस्वीरों ने चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ भी कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता से मिलने का वास्तव में मतलब यह नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। ये निराधार अफवाहें हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि मैं जेडीयू में हूं, जेडीयू कमजोर हो रहा है, लेकिन मैं इसे मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उपेंद्र 17 साल में तीन बार जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और पलट कर फिर वापस लौटे।

गौरतलब हो कि जेडीयू के बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा पर उनकी ही पार्टी के लोग 'आते-जाते' रहने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार तो कई बार यह बात कह चुके। हालांकि नीतीश जब ऐसा कहते हैं तो इसके साथ ही एक बात और शामिल करते हैं। कहते हैं- उनको जहां जाना है, जाएं। इसे समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के अतीत को समझना जरूरी है, वर्तमान तो उनका झमेले में ही पड़ गया है। इधर हिस्सा मांगने की बात पर हालांकि नीतीश ने उन्हें मीडिया के जरिए सुझाव दिया कि वो आमने-सामने बैठकर बात करें। लेकिन ये भी एक मसला है कि एक बार नीतीश के मन से कोई उतर गया तो उतर गया समझिए।

ज्ञात हो कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर 1985 से शुरू हुआ। उन्होंने लेक्चरर की नौकरी छोड़ कर पॉलिटिक्स को नया करियर बनाया। 1985 से 1988 तक युवा लोकदल के वे स्टेट सेक्रेट्री रहे। उसके बाद वे जनता दल का हिस्सा बन गये और 1988 से 1993 तक वे युवा जनता दल के नेशनल जनरल सेक्रेट्री की भूमिका में रहे। 1994 से 2002 तक वे समता पार्टी का हिस्सा रहे। पहली बार सन् 2000 में वे समता पार्टी के टिकट पर बिहार के वैशाली जिले की जंदाहा सीट से एमएलए चुने गये। 2002 से 2004 तक वे बिहार विधानसभा में पार्टी विधायक दल के उपनेता रहे। 2004-05 में उन्हें पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। समता पार्टी जब जेडीयू के रूप में बदली तो 2010 में वे राज्यसभा भेजे गये, जहां 2013 तक रहे। मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) बना ली और 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया। बिहार की तीन लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और उस दौर में मोदी लहर का जादू ऐसा चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा के पाले में जा गिरीं और इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बने। बाद में कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते-आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ढह गई। जिसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला,

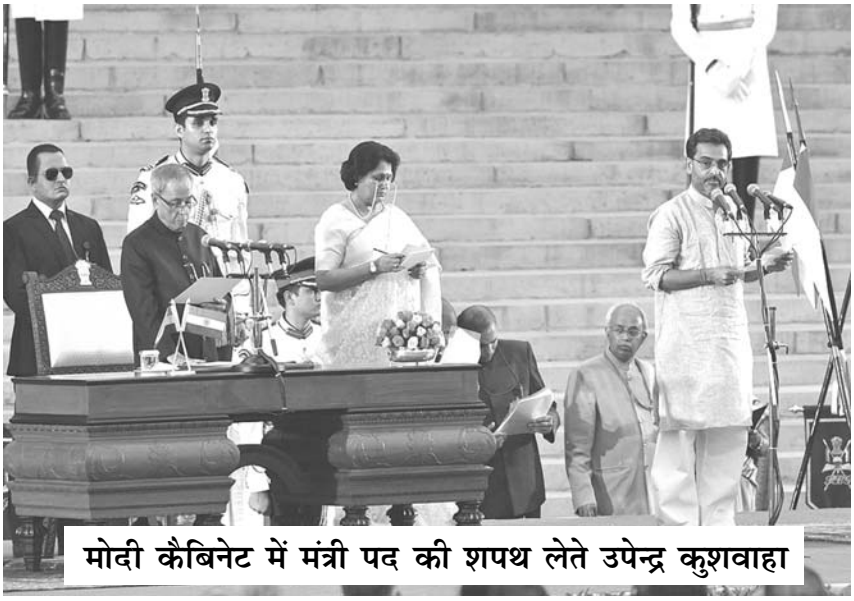

मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेते उपेन्द्र कुशवाहा

लेकिन तब वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। निराशा हाथ लगी। कुछ दिन के लिए एनसीपी के साथ भी रहे। 2021 में वे फिर जेडीयू का रुख किया और अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करा दिया। उन्हें पार्टी में रहकर राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाया गया। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा बिहार के उन नेताओं में शुमार हो गये, जिन्हें चारों सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। दिगर बात है कि हाल ही में बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं तेज हुई तो इस पर उनका जवाब आया कि वो कोई सन्यासी नहीं हैं, लेकिन बाद में जब तस्वीर साफ हुई तो कुशवाहा के हाथ एक बार फिर खाली रहा, जिसके बाद वो खुद को पार्टी में साइडलाइन मानने लगे हैं।

बहरहाल, कुशवाहा अब बड़े भाई से हिस्सा मांगने की जो बात कह रहे, उसके पीछे की कहानी यह है कि जब उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय हो रहा था, तब उन्होंने कहा था- 'नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं।' हालांकि तमाम आरोप-प्रत्यारोपों के बीच ये जानना जरूरी है कि महागठबंधन का हिस्सा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आखिर किस बात से शुरू हुई। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर देखा जाता है। दिसंबर 2022 के महीने में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन के भविष्य का नेता बताया था। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बिहार सरकार में जेडीयू की साझेदार है। जानकारों की राय में गठबंधन में तेजस्वी के बढ़ते कद से कुशवाहा परेशान हैं। बिहार की राजनीति में उनके बयान को इस बात से जोड़ कर देखा गया कि बिहार तेजस्वी के भरोसे छोड़ कर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति का रुख कर सकते हैं। जानकारों का राय है कि नीतीश के तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंपने के बयान से जेडीयू के कई नेताओं की महत्वाकांक्षा को झटका लगा होगा। उनमें सबसे ऊपर उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। उसके बाद से कुशवाहा लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए असहज हालात पैदा कर रहे हैं। वही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि जिस वक्त नीतीश कुमार पर बार-बार हमले हो रहे थे, उस वक्त वह ही सामने आकर उनका बचाव कर रहे थे। उन्होंने नाम लिए बगैर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बार-बार नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। लेकिन कुशवाहा के सुधाकर सिंह के बयानों के खिलाफ

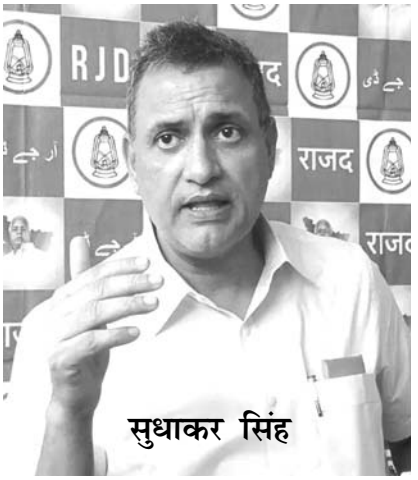

सुधाकर सिंह

खड़े होने को अपना बड़ा काम भले ही बता रहे हों, हकीकत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के बचाव में उतरकर सुधाकर सिंह के बयानों को महत्व दे दिया। इसके पहले न तो आरजेडी और न ही जेडीयू उनके बयानों को बहुत महत्व दे रही थी। तेजस्वी यादव ने तो सुधाकर सिंह के बयानों को 'बीजेपी की भाषा' बताकर खारिज भी कर दिया था। ये तो उनकी नाराजगी की शुरुआत की कहानी है। ये नाराजगी अभी दूर भी नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार के दूसरे बयान ने उपेंद्र कुशवाहा को और ज्यादा नाराज कर दिया। वही कुछ ही दिन पहले बिहार में एक खबर चर्चा में आई थी कि बिहार सरकार में जल्द ही

मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। उसके बाद नीतीश कुमार ने बिना पूछे इस मुद्दे पर बयान दिया था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है और बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा उपमुख्यमंत्री नहीं होगा। यह उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से सीधा इशारा था। दिगर बात है कि 2004 में नीतीश के समर्थन से वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। तभी से उनके मन में सीएम का सपना कुलाचें मारने लगा था। उपेंद्र कुशवाहा का दुर्भाग्य भी साथ ही चलता रहा है। 2004 में नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्हें भरोसा था कि वे एक दिन सीएम, डिप्टी सीएम या कम से कम मंत्री जरूर बनेंगे। 2005 में यह संभव हो सकता था, लेकिन वे चुनाव हार गये थे। जेडीयू-बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन उन्हें तत्काल मंत्री बनाना संभव नहीं था। 2021 में एमएलसी बनने के बाद कुशवाहा को उम्मीद थी कि जब कभी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो उन्हें मंत्री जरूर बनाया जायेगा। दुर्भाग्य से बीजेपी के साथ रहते इस इंतजार में एक साल गुजर गया। बीजेपी का साथ छोड़ नीतीश जब महागठबंधन के साथ चले गये, तब कुशवाहा के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी। पर, यहां भी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर मीडिया ने उनके मन में डिप्टी सीएम का ख्वाब जगा दिया। तर्क भी पुख्ता था कि जब बीजेपी के साथ रहते नीतीश दो डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो इस बार भी संभव है। जब नीतीश ने इस संभावना को खारिज कर दिया तो अब उनकी खीझ बाहर आनी स्वाभाविक थी। बहाने भले दूसरे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का असली कारण उनको मंत्री पद नहीं मिल पाना माना जा सकता है।

Upendra Kushwaha @UpendraKushJDU · 16h
"मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है।"

#Mission_2024

मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है।"

बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रामक एवं अनाप-शनाप खबरें प्रचारित की गई है और की जा रही है। ऐसी अनर्गल बातों को हवा देने वाले महानुभावों को यह मालूम होना चाहिए कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि कई बार अपनी नाराज़गी जताने के लिए बड़े-बड़े पदों को लात जरुर मारी है। इतिहास गवाह है मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है। और इसी आइडियोलॉजी को बर्बाद करने की हो रही साज़िश को नाकाम करने के एक खास मिशन से मैंने अपनी पार्टी का विलय जद (यू.) में करने का फैसला लिया। क्योंकि हमारे सभी साथियों का निष्कर्ष था और है कि राज्य ही नहीं पूरे देश के स्तर पर श्री नीतीश कुमार एक मात्र ऐसे कर्मठ, अनुभवी व साफ छवि के नेता हैं जिनके नेतृत्व में इस विचार धारा को बचाया व बढ़ाया जा सकता है।

बहरहाल, इस पूरे विवाद पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने नाराजगी वाली खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा गया है कि उनके लिए पद से ज्यादा विचारधारा मायने रखती है। वे कहते हैं कि बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह की भ्रामक और अनाप-शनाप खबरें प्रचारित की गई है और की जा रही है। ऐसी अनर्गल बातों को हवा देने वाले महानुभावों को यह मालूम होना चाहिए कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी पद नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी नहीं जताई, बल्कि कई बार अपनी नाराजगी जताने के लिए बड़े-बड़े पदों को लात जरूर मारी है। वहीं उपेंद कुशवाहा मीडिया के सामने आकर पुरानी बातों को याद करते हुए नीतीश कुमार के एक-एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन दो वर्षों में नीतीश ने पांच मिनट भी बात नहीं की। वें अपनी संतान की कसम खाकर कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे, उस दिन हम उनसे बात करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि, "क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल के भीतर होने वाली चर्चाओं को बार-बार बाहर बात करते देखा है? लोगों को पार्टी में मिल कर बात करनी चाहिए। हमारा इतना स्नेह है कि पार्टी से कोई चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।" वही सीएम नीतीश ने कुशवाहा को मीडिया के द्वारा कहा कि ये करोड़ों लोगों के सघंर्ष की पार्टी है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम के 'आए गए' वाले बयान पर कहा कि पार्टी में एक-दो लोगों को छोड़कर कई लोग आए और गए हैं। दो बार हम आए हैं, तीन बार नहीं। उन्होंने कहा कि वें नीतीश कुमार के बुलाने पर ही पार्टी में आए है। उन्होंने वाकया याद दिलाते हुए कहा कि 2009 में 31 अक्टूबर को

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वंय मंच से कहा था कि हमारा उपेंद्र जी से आग्रह है कि वो हमारे साथ आएं, आज वे यह कह रहे हैं कि वो अपने मन से आएं है तो उनका यह कहना गलत है। कुशवाहा ने 2020 की बातों को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम असहाय महसूस कर रहे थे, नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम कितने दिन ही रहेंगे, संभालिए-संभालिए। यह कहना कि जब मन करे आ जाएं और जब मन करे चले जाएं, यह बिल्कुल गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैने आग्रह किया कि हमारी बात मान लीजिए, अभी तो नुकसान की भरपाई संभव है। हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, नीतीश कुमार खुद काम नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2009 में 17 उपचुनावों में बुरी तरह पिट गए थे जेडीयू वाले, तब उपेंद्र कुशवाह याद आए। इस बार 43 सीट पर आ गए, तब उपेंद्र कुशवाहा याद आए। ये जब-जब कमजोर हुए, तब-तब उपेंद्र कुशवाहा याद आए। दिगर बात है कि सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कुशवाहा ने कहा कि उन्हें एमएलसी बनाकर लॉलीपॉप थमा दिया गया, लेकिन उन्हें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। उन्हें ऐसे पद का लालच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा था। नीतीश जी ने जैसे 1994 में लालू यादव से हिस्सा मांगा था, उसी तरह मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सा लिए बगैर खाली हाथ मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्रेस कांफ्रेंस कर उपेंद्र ने कहा, कि नीतीश कुमार कहते हैं की जेडीयू में आने के बाद मुझे बहुत इज्जत दी गई। लेकिन मुझे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष का झुनझुना थमाया गया। जब मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना तो जेडीयू के संविधान में कोई महत्व नहीं था। बाद में जेडीयू के संविधान में संशोधन किया गया। मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाने का अधिकार नहीं मिला। पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव में उम्मीदवारी पर विचार करता है। ये अधिकार भी मुझे नहीं मिला। चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मुझे कोई सुझाव नहीं लिया गया। मैं बिना मांगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश जी को सलाह देता रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पार्टी के नीतिगत फैसले लेनी वाली टीम में अतिपिछड़ा समाज का कोई नेता शामिल नहीं किया गया। उपेंद्र ने कहा कि उन्होंने अतिपिछड़ा समाज से आने वाले पार्टी के किसी नेता को राज्यसभा या विधान परिषद भेजने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वह लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कुशवाहा के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने उनकी चुटकी ली है। भाजपा ने कहा है कि लोग नीतीश के बयान को अच्छे से समझ रहे हैं। जब बीजेपी से 2025 के नेतृत्व के लिए तेजस्वी का नाम आगे बढ़ाने की बात पूछी गई तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी इतनी आगे की बात करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में कहा था कि राजनीतिक रूप से जब-जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, हमने उनको सहयोग करने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा था कि आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के हमले पर नीतीश कुमार खुलकर हमलावर हो गए थे। उन्होंने कुशवाहा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। ये झूठे आरोप हैं। लोगों को जो कहना है, कहने दो। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा था- मैंने किसी को नहीं रोका। नेता अपनी इच्छा से आ और जा सकते हैं। नीतीश के इस पलटवार पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर अपना बयान ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि वे अपना हिस्सा छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप-दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। इसके आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर?

गौरतलब है कि जनता दल (यूनाइटेड) के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बगावत की तुलना उस चुनौती से की जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दशक पहले राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सामने पेश की थी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके मन में 'अगाध श्रद्धा' है, लेकिन नीतीश अपने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। परिणामस्वरूप जेडीयू कमजोर हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि पार्टी में अपने हिस्से का दावा करने से मेरा क्या मतलब है। मैं आज वह कर रहा हूं। मैं उसी हिस्से की बात कर रहा हूं, जो नीतीश कुमार ने 1994 की प्रसिद्ध

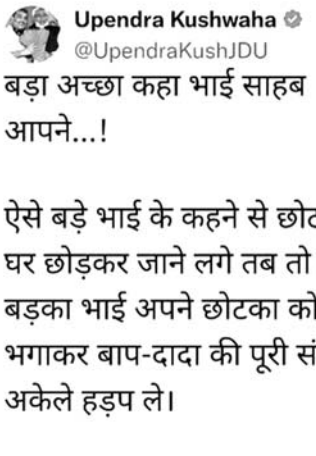

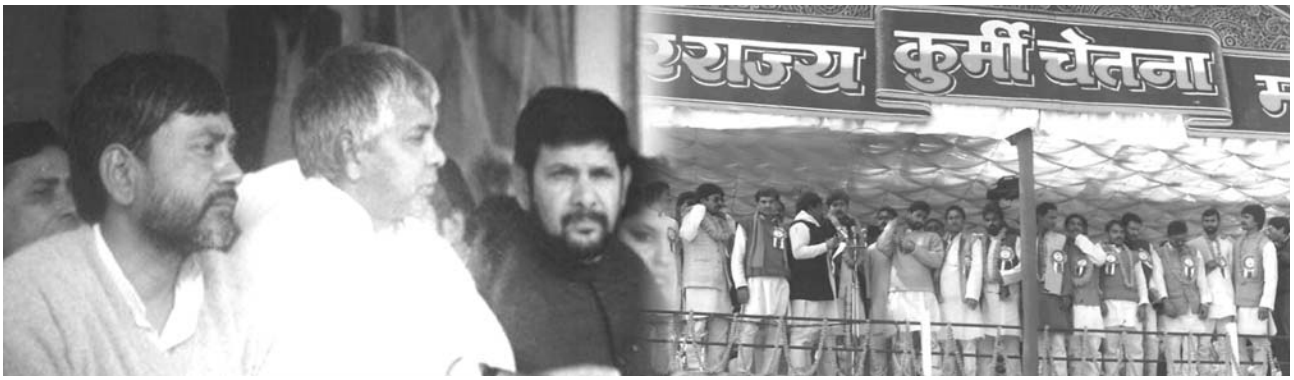

रैली में मांगा था। जब लालू प्रसाद हमारे नेता को उनका हक देने से हिचक रहे थे। कुशवाहा पटना में आयोजित 'लव कुश रैली' का जिक्र कर रहे थे। इसका मकसद बिहार में यादव जाति के राजनीतिक वर्चस्व में पीछे छूटे कुर्मी-कोइरी जाति के लोगों को एकजुट करना था। रैली में नीतीश कुमार की उपस्थिति ने अविभाजित जनता दल से उनके अलग होने और एक स्वतंत्र राजनीतिक यात्रा की रूपरेखा तय की थी। उपेंद्र कुशवाहा मार्च 2017 में अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय करने के बाद जेडीयू में लौटे थे। कुशवाहा ने कहा कि संसदीय बोर्ड के प्रमुख के रूप में उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। यह पद एक तरह का झुनझुना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अतीत में राज्यसभा छोड़ चुका हूं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से भी हट गया था। अगर उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए बड़े विशेषाधिकार हैं, तो पार्टी मेरे सभी पद वापस ले सकती है। विधान परिषद सदस्य का दर्जा भी छीन सकती है। कुशवाहा ने दावा किया कि 2013 के विपरीत जब जेडीयू ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा था, तब बिखराव का खतरा था। ये खतरा अब हमारी पार्टी पर मंडरा रहा है। क्या वह उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी

श्रवण कुमार

यादव के उभार से खतरा महसूस करते हैं, इस सवाल के सीधे जवाब से बचते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह कहना होगा कि मुख्यमंत्री अपने सार्वजनिक बयानों में यह कहते रहे हैं कि उनके सभी कदम, 2017 में बीजेपी के साथ फिर से जुड़ना, पिछले साल अलग होना और महागठबंधन में शामिल होना और यहां तक कि चुनावों में उम्मीदवारों का चयन भी दूसरों के इशारे पर किया गया। वहीं समस्या है। वह अपना निर्णय नहीं ले पा रहे। कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि अति पिछड़ा वर्ग का जेडीयू से मोहभंग हो रहा है। वही दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। मंत्री जयंत राज ने भी कुशवाहा को निशाने पर लिया। कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री कार्यक्रम में जदयू कार्यालय में पत्रकारों के एक सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े नेता हैं और उनको जदयू में जितना सम्मान मिला, उतना कहीं नहीं मिला। श्रवण कुमार ने कहा कि वे (उपेंद्र कुशवाहा) एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान जदयू ने दिया। अब अगर राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष झुनझुना है तो वही बता सकते हैं कि कौन-सा पद झुनझुना नहीं है। जदयू मंत्री ने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा जब-जब जदयू में रहे या आए, सम्मान मिला। हिस्सेदारी तो उनको काफी मिली, बराबरी का दर्जा और सम्मान मिला। और कितना सम्मान चाहिए यह उनको ही बताना चाहिए। वहीं, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जबसे पार्टी में आए हैं उन्होंने पार्टी को कमजोर करने का ही काम किया है। उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप निराधार ही नहीं, हास्यास्पद भी है। वैसे भी झुनझुना पकड़ने की उनकी उम्र नहीं रही, फिर झुनझुना पकड़ाया गया था तो तुरंत छोड़ देते। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद पवेलियन में बैठाने या झुनझुना पकड़ाने वाला है क्या? वही उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बीच कथित सौदे के बारे में सच सामने आना चाहिए और उन्होंने अफवाहों का दौर खत्म करने के लिए पार्टी की तत्काल बैठक की भी मांग की। कुशवाहा ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि वह जद (यू) सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा है। जद (यू) नेता ने नीतीश कुमार को विधानसभा के पटल पर तेजस्वी यादव द्वारा व्यक्तिगत अपमान की याद दिलाने की भी कोशिश की, जब यादव विपक्ष के नेता थे। कुशवाहा ने खुद का बचाव करते हुए कहा, ''मैं नीतीश कुमार की इच्छा के अनुसार पार्टी के मंच पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मेरी एक बात मानी जाए।'' उन्होंने कहा कि ''लंबे समय से मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने की मांग करता रहा हूं। हमारे पास चर्चा करने के लिए मुद्दे हैं। पार्टी कमजोर हो रही है। अफवाह यह है कि आरजेडी के साथ किसी तरह का समझौता हुआ है। इस पर पार्टी फोरम में चर्चा होनी चाहिए। यह अनुमान लगाया

जयंत राज

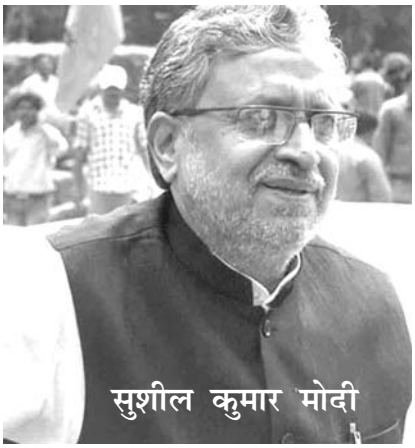
सुशील कुमार मोदी

जा रहा था कि बिहार की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भविष्य में किसी भी वक्त यादव को सब कुछ सौंपकर अपनी ऊर्जा राष्ट्रीय राजनीति में लगाने को तैयार हो गए हैं। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि ''मेरे सामने एक ही विकल्प था- सीधे मुख्यमंत्री से बात करना। मैं दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पार्टी की कमजोरियों को उजागर करने के लिए उनसे मिला था। उन्होंने मुझे यह कहकर झिड़क दिया कि क्या मैं बीजेपी से हाथ मिलाने के बारे में सोच रहा हूं।' जद (यू) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने नीतीश कुमार के बार-बार यह कहे जाने पर पर प्रतिक्रिया दी कि कुशवाहा ''जितनी जल्दी हो सके, जहां भी जाना चाहते हैं, जाने के लिए स्वतंत्र हैं।'' उन्होंने कहा कि ''मैं इस संगठन के साथ अपने पिछले अवतार 'समता पार्टी' के साथ हूं। मैं सिर्फ इसलिए पार्टी नहीं छोड़ूंगा कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है।'' बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सुप्रीम लीडर हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावत करने से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा? यानि कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा? पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2025 के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी जेडीयू का उत्तराधिकारी तय नहीं किया है। सुशील मोदी का कहना है कि इससे जेडीयू विधायकों का भविष्य खतरे में हैं। नीतीश कुमार बार-बार कहते हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। ऐसे में उन्हें तेजस्वी यादव या अपनी ही पार्टी के किसी नेता को सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। जेडीयू विधायक अगला चुनाव किसके चेहरे पर जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेडीयू का उत्तराधिकारी भी तय करना चाहिए। आरजेडी के 60 से ज्यादा विधायक अभी ऐसे हैं, जो पिछले चुनाव में जेडीयू को हराकर विधानसभा पहुंचे। इन सीटों पर जेडीयू का भविष्य अंधेरे में है। वही साल 2021 में जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय किया गया था, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश के बाद पार्टी की कमान वे ही संभालेंगे। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश और पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। वे कई बार मीडिया के सामने खुद को जेडीयू में साइडलाइन किए जाने के आरोप लगा चुके हैं। उनकी जेडीयू से विदाई तय मानी जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर गए तो किसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? दूसरी ओर, किसी समय जेडीयू के बड़े नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह भी पिछले साल पार्टी छोड़ दी। एक समय में वे भी नीतीश के उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। आरसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। बीजेपी से नजदीकियों की वजह से उनका नीतीश कुमार से विवाद हुआ। जेडीयू ने उन्हें दोबारा राज्यसभा सांसद नहीं बनाया, इस वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी।

बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में लगातार विवाद जारी है। दोनों लगातार एक-दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। कभी नाम लेकर तो कभी इशारे-इशारे में ही ये खींचतान जारी है। बात यहां तक पहुंच गई है, अब लग रहा है कि ये कुशवाहा के इस्तीफे की ओर जाएगी। असल में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में 'इस्तीफे' शब्द का प्रयोग किया और कहा कि कुशवाहा को खुद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा था कि ऐसे कैसे चलें जाएं, कोई अपना हिस्सा-अपनी संपत्ति छोड़ कर कैसे जा सकता है। इस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश के दिए उस बयान का जवाब दिया था, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि 'जहां जाना है वहां चले जाएं, कोई आता है, किसी को बढ़ा देते हैं, कोई भाग जाता है, कोई जाना चाहता है, हमको क्या है, पार्टी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है'। उमेश कुशवाहा जमकर उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को तो

उमेश कुशवाहा

शर्म आनी चाहिए। उन्हें तो खुद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कुशवाहा पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा का कोई भागेदारी और हिस्सेदारी नहीं है, उनकी तो कोई जमीन भी नहीं है। वह जबसे जदयू में आए हैं, सिर्फ पार्टी को कमजोर ही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में रहते हुए अभी महात्मा फुले संगठन चला रहे हैं। इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका क्या औचित्य है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले पार्टी की मजबूती की बात कर रहे थे और अब पार्टी में ही हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। दिगर बात है कि बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खूब कयासबाजी चल रही है। कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाए जाने से वह नाराज चल रहे हैं। शरद यादव के निधन के बाद जब वह श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनकी नाराजगी साफ-साफ झलक भी रही थी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा था कि जिस शरद यादव ने देश में कई नेताओं को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया, उन्होंने आखिरी वक्त में उनसे मुंह मोड़ लिया था। भगवान ऐसा अंत किसी को न दें। उनका सीधा इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ था। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू ने भी मन बना लिया है। जेडीयू के उच्च सूत्रों का कहना है कि कुशवाहा करीब छः महीने तक नीतीश कुमार के पास अपनी सियासी वजूद बचाने के लिए दौड़े थे। हमारे नेता ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। उन्हें एमएलसी बनाया और जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया। उनकी महत्वकांक्षा यहीं नहीं रुकी। मंत्री बनने की उनकी लालसा ने

उन्हें भटका दिया है। यही वजह है कि वह इस तरह के बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को तोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हाथ है। वह लगातार गठबंधन विरोधी बयान दे रहे थे। हमारी पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मन बना लिया है। वह अपने सियासी जीवन को लेकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें जेडीयू में काफी सम्मान मिला। वही अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होने बांका में समाधान यात्रा के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रहकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें मैंने कई बार मौके दिए। कई बार पार्टी में आए और गए, इसके बावजूद मैंने उन्हें सम्मान दिया। लेकिन बीते 2 महीने से वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो किसके इशारे पर हो रही है। आप सब जानते ही हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी को दोषी बताते हुए उन्होने कहा कि अगर कोई किसी का प्रचार इस तरह कर रहा है। तो समझ जाइए खेल कहां से खेला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पर कोई निर्णय लेने के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि वर्तमान में अभी पार्टी उन पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्हें जो निर्णय लेना है वो खुद ही लें।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदेह जताया कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। उन्होंने कुशवाहा के उस दावे को खारिज किया कि पार्टी हाल के दिनों में ''कमजोर'' हो गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के संपर्क में हैं। कुमार ने कहा, ''उन्हें कम से कम एक नेता का नाम लेना चाहिए जो संपर्क में है। जो खुद संपर्क करना चाहते हैं, वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के कमजोर होने संबंधी कुशवाहा के दावे को खारिज करते हुए कहा कि नवीनतम

सदस्यता अभियान में हमारी संख्या 50 लाख से बढ़कर 75 लाख हो गई है। बीते दिनों कुशवाहा चिकित्सा जांच के लिए दिल्ली में थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भाजपा के कुछ नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थीं। ऐसा माना गया था कि इन तस्वीरों को कुशवाहा के समर्थन में जानबूझकर सोशल मीडिया पर डाला गया है। कुमार ने एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से कहा, ''अगर उनकी कोई अधूरी महत्वाकांक्षा है तो उन्होंने इस संबंध में मुझे कभी नहीं बताया। वह जहां चाहे जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के कहने पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बयानों पर बात करने की जरूरत नहीं है। वो बार-बार ऐसे बयान दे रहे हैं, मतलब उन्हें कोई और चला रहा है। उन्होंने कहा कि हमने उस आदमी को कितना बढ़ाया है। एमएलए बनाया, हम लोगों ने अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाया। फिर भाग गया। फिर एक बार आ गया, राज्यसभा सांसद भी बना दिया, फिर भाग गया। तीसरी बार आ गया। तीसरी बार आया तो बोला कि हर हाल में रहेंगे। कुशवाहा जब आए तो हमने सब दे दिया लेकिन, अब हमको आश्चर्य हो रहा है। कहा है कि हम बात करें कि आप बात करेंगे। वो बात ही नहीं कर रहा है और उसको इज्जत देते रहे। फिर क्या हो गया। अचानक यह सब 2 महीने के अंदर हुआ है। रोज बोलने का मतलब क्या है। इसके प्रचार का मतलब अब समझिए, इसका प्रचार कौन कर रहा है। हमारी पार्टी में कोई बोलेगा? उसका प्रचार नहीं होगा। आप जरूर समझे कि वह किसी और के लिए बोल रहा है। तो प्रचार हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि उसको जो इच्छा है वह करें। हमने तीसरी बार उसको एक्सेप्ट किया है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या यह भाजपा की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आप समझ लीजिए, प्रचार किया जा रहा है। तो आप समझिए, जब किसी का प्रचार होता है तो आप समझ जाइये, कहां से प्रचार होता है? कौन मौका दे रहा है? हम लोगों के अध्यक्ष ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया है कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों को मालूम है क्या स्थिति है? पार्टी के पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुए। पार्टी कमजोर नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं जो लोग छोड़कर जा रहे हैं। इससे पार्टी को कुछ नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी को एक बार किसी ने नुकसान किया वह जिसके साथ हम 2017 में आए थे। 2019 में हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा, हम लोगों ने कहा कि भाई, तीन-चार तो दीजिएगा ना मंत्रिमंडल में। लेकिन, वह एक ही दे रहे थे। तब हमने कहा कि नहीं लेंगे। उसके बाद जब विधानसभा का क्या हुआ। उसे कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई आता है आए, कोई जाता है जाए। जिसको जहां जाना हो, जितनी जल्दी जाना हो चले जाए।

तेजस्वी यादव

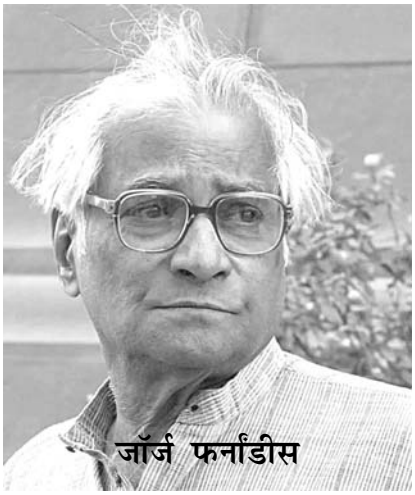
जॉर्ज फर्नांडीस

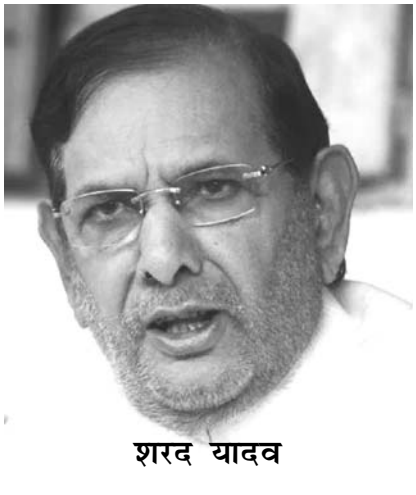
शरद यादव

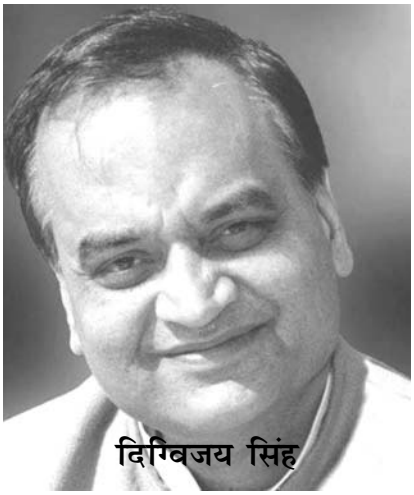
दिग्विजय सिंह

हालांकि यहां उन्हें सम्मान मिलता है। कुशवाहा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ''कभी भी भाजपा के सदस्य नहीं बनेंगे'' लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक पार्टी बनाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने संबंधी सवाल को उन्होंने टाल दिया।

बहरहाल, कुशवाहा और नीतीश में जारी जंग के बीच सवाल उठ रहा है कि जेडीयू हाईकमान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जेडीयू से उपेक्षित महसूस कर रहे उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? नीतीश कुमार को बड़ा भाई कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा उन पर इतने गुस्से में क्यों हैं? यह सवाल इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि 2 बार जेडीयू छोड़ने वाले कुशवाहा की वापसी नीतीश ने ही कराया था। कुशवाहा के गुस्से में होने की 3 वजह अब तक सामने आ रही है। पहला कि उपेंद्र कुशवाहा खुद को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मानते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने से उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। दूसरा कि जेडीयू में शामिल होने के बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाएंगे, लेकिन डेढ़ साल बाद भी उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है और तीसरा कि कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इसकी हरी झंडी नहीं दी है। वही उपेंद्र कुशवाहा के बागी रूख को देखते हुए नीतीश कुमार ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। नीतीश ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जाने का मन है, तो जा सकते हैं। नीतीश के इस बयान का सीधा मतलब है कि कुशवाहा उनके मिशन में फिट नहीं है। नीतीश लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए मिशन 2024 में जुटे हैं। इसके लिए जातीय समीकरण से लेकर संगठन और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए हैं। ऐसे में कुशवाहा की बगावत ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन दोनों बार सियासी हिट-विकेट भी हो चुके हैं। कुशवाहा इसलिए इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। खुद से निकलने पर समर्थकों से इमोशनल अपील करने का भी मौका हाथ से चला जाएगा। ऐसे में 2024 में शायद ही कुशवाहा असरदार रह सके। कुशवाहा समर्थकों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री इस बार जेडीयू हाईकमान की ओर से कार्रवाई के इंतजार में हैं। उपेंद्र कुशवाहा भले जेडीयू हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन आगे की उनकी रणनीति साफ नहीं है। ऐसे में जेडीयू की इस आंतरिक लड़ाई में बीजेपी भी नहीं कूदना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक जब तक कुशवाहा को किसी बड़े दल से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वे शायद ही बगावत करें। दिगर बात है कि कुशवाहा के पार्टी से नहीं निकलने की वजह तो समझ आ रही है, लेकिन लगातार पार्टी हाईकमान के खिलाफ मुखर कुशवाहा पर जेडीयू क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इसका पहला कारण है कि नीतीश कुमार जेडीयू से अब तक जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, पी.के. शाही, शरद यादव, नरेंद्र सिंह, शकुनी चौधरी और आरसीपी सिंह को हटा चुके हैं। सबसे दिलचस्प है कि नीतीश ने अब तक एक भी नेताओं को सीधे बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। इसकी बड़ी वजह है कि जनता के बीच खुद को पीड़ित दिखाने की। नीतीश कुमार किसी भी नेता को पार्टी से निकालकर जनता के बीच इमोशनल अपील करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कुशवाहा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा कारण कुशवाहा जाति नीतीश का आधार वोटर्स कहा जा सकता है। बिहार में कुशवाहा वोटर्स करीब 3-4 फीसदी के बीच में है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2014 में करीब 3 फीसदी वोट मिला था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी आधार वोटर्स कुर्मी और कुशवाहा है। नीतीश ने इसी समीकरण को साधने के लिए 2020 के बाद उमेश कुशवाहा को प्रदेश की कमान और उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से सीधा निकालकर नीतीश, कुशवाहा समुदाय का वोटर्स से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। उधर नीतीश कुमार द्वारा 'जिसे जाना है जाए' के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अपना हिस्सा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंन ट्वीट किया, ''बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने...! ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगा तब तो हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को घर से भगाकर बाप-दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प

आर.सी.पी. सिंह

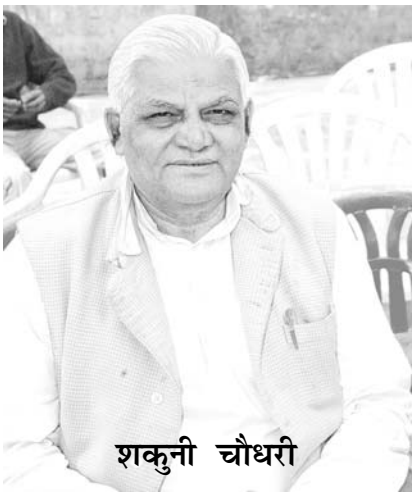
शकुनी चौधरी

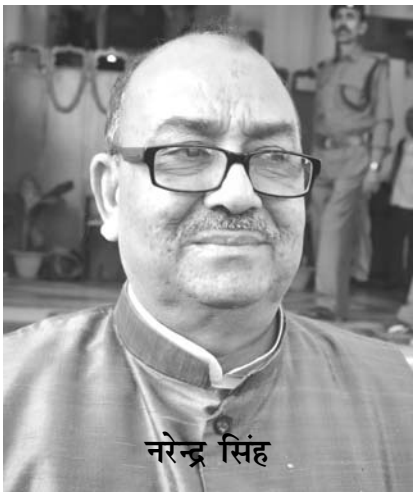
नरेन्द्र सिंह

पी.के. शाही

लेगा। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? वही बीते दिनों कुशवाहा ने एक दैनिक अखबार से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वह जदयू में हैं और जदयू में ही रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, वह उनकी अपनी जुबान नहीं है। उनको लोग जो सीखा रहे हैं, वो वही बोल रहे हैं। वहीं ललन सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो इतने दिनों से मेरे नाम के नीचे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष लिख रही थी, क्या वह झूठ है? वही कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कि यह पार्टी नहीं है। यह शरद यादव की पार्टी है, जिसको उन्होंने धकिया कर बाहर निकाल दिया था। मुझे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ललन सिंह कह रहे हैं कि सभापति इस पर निर्णय लेंगे? सभापति निर्णय लेंगे तो लेंगे। उस पर कुछ नहीं कहना है।

गौरतलब है कि नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सियासी द्वंद के हाल फिलहाल

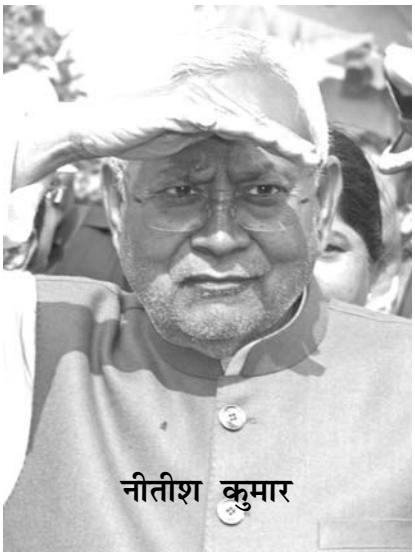
नीतीश कुमार

में थमने की आशंका कम है। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार होना है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं में सियासी बयानबाजी और अधिक बढ़ सकती है। कुशवाहा के साथ वर्तमान में ना तो एक भी विधायक है और ना ही संगठन का कोई बड़ा नेता उनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कोई दूसरी पार्टी भी उन्हें शायद ही हाथों-हाथ ले। ऐसे कुशवाहा भी बयानों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते रहेंगे। जेडीयू भी उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का लक्ष्मण रेखा माप रही है। नीतीश के खिलाफ विवादित बयान देने पर ही उन्हें नोटिस थमाया जाएगा। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि खरमास के बाद जेडीयू में शुरू हुई खटपट कब खत्म होगी? इधर जेडीयू में जारी घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बतौर पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष दो दिन बैठक बुलाई है। यह बैठक 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में होगी। कुशवाहा ने जेडीयू के लेटर पैड पर अपने हस्ताक्षर से लिखा पत्र ट्विटर पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की हुई डील का जिक्र करते हुए कहा कि इसने जेडीयू कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया है। इस पर चर्चा के लिए वह बैठक बुला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 'जेडीयू के कर्मठ, समर्पित एवं महत्वपूर्ण साथियों के नाम पत्र' के माध्यम से अपील की है कि 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में चर्चा में भाग लें। कुशवाहा ने अपने पत्र में कहा है कि आरजेडी की ओर से एक खास डील और जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं, कार्यकर्ताओं वरन आम जनमानस को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सबके समक्ष राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर

उक्त विषय पर चर्चा करें। कुशवाहा ने अपने पत्र में दावा किया है कि जेडीयू अपने आंतरिक कारणों से रोज कमजोर होती जा रही है। उनकी बातों की न सिर्फ अनदेखी की जा रही है बल्कि उसकी व्याख्या भी गलत तरीके से की जा रही है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर जेडीयू बिखर गई तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा? उधर पार्टी अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि उनकी कोई भी इच्छा हो उसे पार्टी के मंच पर उठाना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा सही तथ्य रखने चाहिए। वहीं पार्टी से नाराज चल रहे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक खुला पत्र लिखकर पार्टी के लगातार कमजोर होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होने 19 एवं 20 फरवरी को पार्टी नेताओं की एक बैठक रखी है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बताएंगे कि उनकी

जनता दल (यूनाइटेड)

कार्यालय- 07, अंजर नगर रोड, नई दिल्ली- 110001.

प्रिय साथी,

हमारी पार्टी अपने आंतरिक कारणों से रोज व रोज कमजोर होती जा रही है। महा गठबंधन बनने के बाद हुए विधानसभा उप चुनावों के परिणाम अपने के समय से ही ये पार्टी की स्थिति से भी मुख्यमंत्री जी को लगातार अवगत कराने का रहा हूं। सबब -सबब पर पार्टी की बैठकों में भी मेरे अपनी बातें रखी है। विगत एक-डेढ़ महिने से मेरे हर संबंध समिति से कोशिश की है कि विसंगतियां अपना अस्तित्व खोती जा रही पार्टी को बचाया जा सकेगी कोशिश आज भी जारी है। परन्तु समाज प्रयासों के बावजूद मा मुख्यमंत्री जी की ओर से मेरी बातों की न सिर्फ अनदेखी की जा रही है बल्कि उसकी व्याख्या भी गलत तरीके से की जा रही है।मेरी चिंता और जहां तक मैं समझता हूं आप सभी की चिंता भी इस बात को लेकर है कि अगर जदयू बिखरा तथा तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके अरमान इस दल के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहकर और अपनी कुर्बानी देकर इसके निर्माण में अपना योगदान किया है।

साथ ही राजद की ओर से "लाक डाउन डील" और जद (यू.) का राजद के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं कार्यकर्ताओं वरन आम जन मानस को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सबके समक्ष राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनती जा रही है।

अतः आज आवश्यकता इस बात की आ गई है कि हम सब मिलकर उक्त विषय पर विमर्श करें।
इस हेतु आप से आग्रह है कि अपने साथियों के साथ निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार उपस्थित हो कर चर्चा में भाग लेने का कष्ट करेंगे।

कार्यक्रम का विवरण:-

बैठक की तारीख:- 19 एवं 20 फरवरी 2023.

समय:- 11 बजे से

स्थान:- सिन्हा लाईब्रेरी, पटना। (बिहार विधानसभा परीक्षा समिति के बगल में)

आपका,
(उपेन्द्र कुशवाहा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
पार्लियामेंट्री बोर्ड, जद (यू.)

सेवा में,
जनता दल (यू.) के प्रमुख साथी,
पूर्व में राजनीतिक के साथ काम कर चुके प्रमुख साथी,
कहलगांव चुके समता परिषद् के प्रमुख साथी।

क्या इच्छा है। अगर उनकी मंशा साफ होती तो वो पार्टी के मंच पर अपनी बात को रखते, लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ अलग मामला है। भविष्य कि उनकी क्या रणनीति है वो वही बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उपेक्षा करने के लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि बिहार विधान परिषद का सदस्य होना लॉलीपॉप नहीं है। ये पद अगर उन्हें दिया गया तो उनकी सहमति से उन्हें दिया गया है। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा गलत तथ्यों को रख रहे हैं। राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन हो या विधानपरिषद के उम्मीदवारों के चयन का मामला हो मैंने स्वयं उनसे मिलकर बात की है। उनकी रणनीति कुछ भी हो लेकिन उन्हें गलत तथ्य नहीं रखने चाहिए। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पूर्व ही मैंने उनसे चर्चा की थी। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार जनता दल यूनाइटेड में स्वयं की उपेक्षा की बात करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, उन्होंने मीडिया के सामने कई बार इसका जिक्र किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर राजद में पार्टी के विलय की चर्चा पर पार्टी नेताओं से सफाई मांगी है। साथ ही उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन भी 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाईब्रेरी में रखा है।

दिगर बात हो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल,

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 175) पटना, बुधवार 17 मार्च 2021

निर्वाचन विभाग

ज्ञापांक 1pui

17 मार्च 2021

सं0 बी1-3-4/2020-15—लोक सविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) एवं खण्ड (5) के अधीन बिहार के राज्यपाल द्वारा दिनांक 24.05.2020, 27.05.2019 एवं 31.05.2016 को अपने कार्यालय की स्थापित एवं संवीक्षित/पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में रिक्त 12 (बारह) स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ मनोनयन किया जा चुका है;

इसलिए निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-बी1-3-4/2020-14 दिनांक 17.03.2021 के क्रम में अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 74 के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 (बारह) सदस्यों का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किये जाते हैं;

1. श्री अशोक चौधरी
2. श्री जनक राम
3. श्री रामेश्व कुशवाहा
4. डॉ0 (डा0) राम वचन राय
5. श्री संजय कुमार सिंह
6. श्री ललन कुमार सर्राफ
7. डॉ0 (डा0) संजेय प्रसाद गुप्ता
8. श्री संजय सिंह
9. श्री देवेश कुमार
10. डॉ0 प्रमोद कुमार
11. श्री रामचन्द्र ठाकुर
12. श्रीमती निवेदिता सिंह

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निखिल कुमार साहू,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

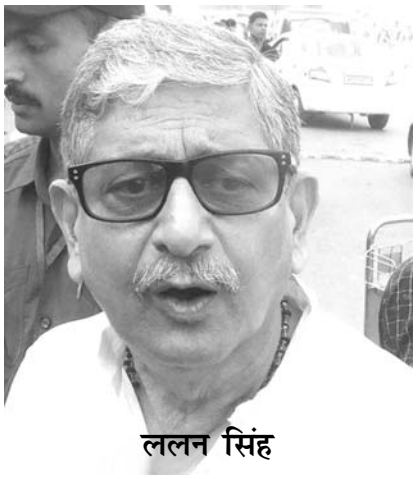
ललन सिंह

कुशवाहा अपनी रणनीति के तहत हर रोज कोई न कोई सवाल उठाकर जेडीयू को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब 19 और 20 फरवरी को जेडीयू कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने जा रहे हैं। इस बाबत उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है। अब ललन सिंह ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा को जेडीयू में पूरा सम्मान दिया गया। लेकिन, अब वह भ्रम फैला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र और दो दिवसीय बैठक बुलाने को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 'कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना' करार दिया है। इसी शीर्षक से कुशवाहा के पत्र को टैग कर उन्होंने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया ट्वीट की। ललन सिंह ने उपेंद्र के इस कदम को जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास बताया और कहा कि कुशवाहा ने दो दिवसीय बैठक में जिस विषय को चर्चा के लिए तय किया है, उसपर स्पष्ट तौर पर कहा कि ना कोई डील है और ना ही विलय की बात, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। इससे पूर्व जेडीयू मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा किस हक की बात कर रहे हैं समझ से परे है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में झुनझुना थमाए जाने के आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा, ऐसा नहीं है। जब से पार्टी में आए हैं, जितना सम्मान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को मिलना चाहिए, पूर्ण सम्मान हम लोग देते रहे। पार्टी के अंदर जब भी उनको कोई समस्या आई और जब भी हमसे कहा, समस्या का निदान हमने किया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो भी उम्मीदवारों का चयन हुआ सबमें उनका परामर्श लिया गया। पार्टी की नाराजगी तथा नोटिस भेजे जाने को मीडिया द्वारा उड़ाई गई बात बताई। कुशवाहा पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि कोई कार्रवाई आखिर क्यों की जाएगी। हमलोग क्यों नाराज रहेंगे किसी साथी से? पार्टी के अंदर हर साथी को उचित सम्मान व काम मिलता है। हमें नहीं पता वे बीजेपी में जा रहे हैं, ये तो रामचन्द्र बाबू से जाकर पूछते? उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती से चल रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। सनद् रहे कि एक तरफ नोटिस और कार्यवाई को मीडिया की अफवाह बताने वाले पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा झटका दे दिया है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मचे घमासान के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक और बड़ा दावा करके कुशवाहा की टेंशन और बढ़ा दी है। ललन सिंह जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा है कि वे पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। फिलहाल यह पद रिक्त है। पार्टी में केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। चुनाव बाद केंद्रीय कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कुशवाहा अब केवल एमएलसी हैं। पार्टी में मन से रहते हैं तो फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाये जाएंगे। वही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी में कुछ बचा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर रहे थे। इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को कभी भी जदयू में मिलने नहीं दिया, उनको महात्मा फुले समता परिषद में रखा। अब उनके लिए पार्टी में क्या है, वह पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के मर्यादा को तार-तार कर दिया है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बदनामी की है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं वह हमारे साथ हैं। उनके बुलाने पर कोई नहीं जाएगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहा जाना कि जदयू नीतीश की पार्टी नहीं है पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वह वार्ड सदस्य का भी चुनाव जीतकर दिखाएं, यह मेरा चौलेंज है उनको। उन्होंने कहा कि उनके गांव में जाकर पता कर लीजिए उनकी क्या हैसियत है। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर थोड़ी भी शर्म है तो वह अपनी अनैतिकता दिखाएं। वही जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब पार्टी में हैं ही नहीं। वह तो विपक्ष

में हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच चल रहे सियासी घमासान में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कूद पड़े हैं। इस घमासान को लेकर पार्टी के कुछ नेता नीतीश कुमार के समर्थन में हैं वहीं, कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भी आ रहे हैं। पटना में एक समाचार चैनल से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा के उपेंद्र कुशवाहा अब विपक्ष में है और विपक्षियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। वह अब पार्टी में नहीं है। एक सवाल के जवाब में उमेश कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि जो पार्टी में नहीं है उसके बयान पर नोटिस क्या लिया जाए। जो विरोधी हैं और विपक्ष में हैं वह तो ऐसा बोलेंगे ही। उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई कब होगी? उन्होंने कहा कि समय पर सब कार्रवाई होगी। गौरतलब हो कि उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि ललन सिंह कह रहे हैं कि आप सिर्फ एमएलसी रह गए हैं, का जवाब देते हुए कहा कि ललन सिंह अपनी ही बात को काट रहे है। अब तक जदयू कार्यालय से जो भी रिलीज जारी हुआ, उसमें मेरा नाम लिखा रहता था। कुछ महीने पहले जब ललन जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें भी मेरा नाम लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो शामिल कर लिया, लेकिन व्यावहारिक तरीके से अलग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मुझे झुनझुना थमा दिया। मेरी इन बातों को ललन सिंह ने प्रमाणित कर दिया।

बहरहाल, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच छिड़ी जंग को लेकर अब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने

उमेश कुशवाहा

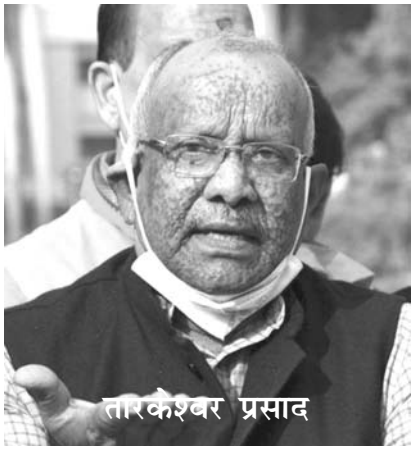

तारकेश्वर प्रसाद

आया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसी भी दल में कार्यकर्ताओं और नेताओं की सहभागिता होती है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, जब उनकी ऐसी पीड़ा है तो सामान्य कार्यकर्ता, सांसद और विधायकों पर क्या बीत रही होगी, कल्पना कीजिए। वही बीजेपी में होगी उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री के सवाल के जवाब में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अगर वो भाजपा में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जासवाल ने कहा कि नीतीश कुमार, लालू परिवार की गुलामी कर रहे हैं। मगर उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी गुलामी करें, यह जरूरी नहीं है। नीतीश के महागठबंधन में जाने से नाराज सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने कुशवाहा को खुला ऑफर दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं। भले ही उन्होंने दल बदल लिया हो, लेकिन अभी दिल नहीं बदला है। कुशवाहा से एक दिन पहले दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में बिहार बीजेपी के तीन नेताओं ने मुलाकात की थी। इनमें प्रेम रंजन पटेल समेत संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान शामिल हैं। प्रेम रंजन पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कुशवाहा की तबीयत खराब होने पर वह उनसे मिलने एम्स गए थे। वे उनके पुराने साथी रहे हैं इसलिए हालचाल जानने पहुंचे। उनसे कुछ मुद्दों पर बात भी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 1990 से 2005 के बीच जंगलराज के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नीतीश के करीबी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। हालांकि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा खुद बड़ी ताकत नहीं रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और

संजय जायसवाल

2020 के विधानसभा चुनावों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। बीजेपी से लगतार उसके सहयोगी अलग हो रहे हैं। शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू के अलग होने से बीजेपी के सामने एक सवाल रखा जा सकता है कि वो सहयोगियों के लिए सही पार्टी नहीं है, इसलिए वो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में वापस ले सकते हैं। कुशवाहा खुद बीजेपी में शामिल होंगे, इसकी संभावना कम है, वो फिर से पार्टी बनाकर गठबंधन कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं लगता है कि ये अगले कुछ दिनों में ही हो जाएगा। वहीं बिहार में कुशवाहा वोटर मुश्किल से तीन फीसदी होंगे, हालाँकि अब बिहार में मंडल कमिशन वाली 1990 के दशक वाली जातीय राजनीति नहीं होती है, फिर भी अगर वो बीजेपी से जुड़ते हैं तो चुनावों के समय बीजेपी के पास दिखाने के लिए एक नेता होगा और वो जनता को संदेश दे सकती है कि हमारे पास भी लोग आ रहे हैं।

सनद् रहे कि बिहार की राजनीति में अब यह साफ हो चला है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर जदयू कार्रवाई करेगी। इस बाबत पूरी प्रक्रिया का ख्याल रखते हुए उन्हें नोटिस भेजे जाने को लेकर तैयारी चल रही है। नोटिस के जवाब के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। उपेंद्र कुशवाहा को जो नोटिस भेजा जा रहा है, उसमें सबसे पहले इस बात का जिक्र है कि उन्होंने पार्टी की ओर से आयोजित शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती में भाग नहीं लेकर किसी दूसरे संगठन की ओर से आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग क्यों लिया? इस संबंध में पहले ही पार्टी की ओर से साफ-साफ कह दिया गया था कि पार्टी से जुड़ा व्यक्ति पार्टी के आयोजन में ही शामिल हो। इसके अतिरिक्त हाल के दिनों में लगातार प्रेस कांफ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जिस तरह से

टिप्पणी की है, उसे भी जदयू अनुशासनहीनता मानता है। जदयू से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यह बात भी कही जा रही है कि जिन बातों को पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए था उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कांफ्रेंस में कहा। पार्टी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। ऐसी संभावना है कि जदयू की ओर से जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस भेजा जाएगा। एक तय अवधि तक उन्हें जबाव देने के लिए कहा जाएगा। अगर उनका जबाव नहीं आता है तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। इधर, उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू की ओर से नोटिस भेजे जाने की तैयारी के बीच कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा है। पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं। यह न मेरी है और न किसी और की। यह किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। उपेंद्र ने कहा कि वह तो सिर्फ पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं। पार्टी अगर नहीं बची तो सभी का नुकसान होगा। जब राजद के नेता यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दें तो फिर जदयू के नेता इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे। इस डील को सार्वजनिक करने की बात ही तो मैंने की है। नीतीश कुमार ने जिस दिन यह कहा था कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो इस बारे में पार्टी के सभी नेताओं से चर्चा होनी चाहिए थी।

बहरहाल, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि वह बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि, उनके दावों में दम नहीं है। ऐसा इसलिए कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहते हुए ही उनके संबंध बीजेपी से खराब हो गए थे। इसके बाद बीजेपी भी यह मानती है कि गठबंधन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को उकसाने वालों में कुशवाहा भी शामिल थे। इसके अलावा, आरजेडी से उनके संबंध पहले से ही ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जेडीयू से बाहर निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा आखिर कहां जाएंगे। अब तो यह तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में नहीं रह पायेंगे। खुद जायें या जाने पर जेडीयू उन्हें मजबूर कर दे। ऐसे में उनके सामने सिर्फ बीजेपी का घर दिखता है। बीजेपी भी उन्हें महज जेडीयू के एक नेता के रूप में शामिल करायेगी। ऐसे में कुशवाहा को 2014 की तरह बीजेपी भाव देगी, इसमें संदेह लगता है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। कुशवाहा के सामने बीजेपी में अपने को

साबित करने के लिए टास्क भी टफ होंगे। उन्हें जेडीयू को कमजोर करने के लिए उसे तोड़ना होगा। साथ ही वैसे तमाम काम करने होंगे, जिससे जेडीयू कमजोर हो। अभी जो बातें वे कह रहे हैं, उसे जेडीयू को कमजोर करने की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। शायद नीतीश इसे भांप चुके हैं। इसीलिए बार-बार उनको चले जाने के लिए ललकार रहे हैं। विडम्बना देखिए कि देश की राजनीति में बिहार कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है। इन सबके केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता उनपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार से पार्टी में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की राह पर चलेंगे? नीतीश कुमार की तरह ही क्या कुशवाहा भी जेडीयू से अलग होकर दोबारा बीजेपी के पास जाएंगे? जाहिर तौर पर विपक्ष में बैठी बीजेपी कुशवाहा को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। बिहार में तीन सक्रिय राजनीतिक दल हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और बीजेपी। राज्य में ज्यादातर देखा गया है कि इन तीन पार्टियों में से कोई दो पार्टी गठबंधन करके सरकार बना लेती है। जेडीयू-बीजेपी की सरकार, जेडीयू-आरजेडी की सरकार इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास मौजूदा विकल्प की। जाहिर तौर पर कुशवाहा जेडीयू में अलग-थलग पड़ चुके हैं। उनके पास पार्टी में अब कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे में उनके सामने विकल्प के तौर पर बीजेपी है। 2024 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी बिहार में ऐसे नेता का साथ जरूर चाहेगी। बीजेपी को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाला बड़ा ओबीसी चेहरा भी मिल जाएगा। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से खड़ी कर सकते हैं। हालांकि आरएलएसपी का जदयू में विलय कर दिया गया था लेकिन, उपेंद्र कुशवाहा इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को साथ में लेकर बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया था। आरएलएसपी को 3 सीट मिली थी और जदयू की करारी हार हुई। इसलिए कुशवाहा आरएलएसपी को आगे बढ़ा सकते हैं बशर्ते जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के साथ चल रही उनकी लड़ाई खत्म हो जाए। इसलिए इस पार्टी को खड़ा करना इतना आसान कुशवाहा के लिए नहीं होगा। कुशवाहा के पास एक तीसरा विकल्प भी है। वह है नई पार्टी बनाना। पुरानी पार्टी को खड़ा करने में कानूनी दांवपेच का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बना कर आगे की राजनीति खेल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अपने ओबीसी समाज में बड़ी पकड़ है। नीतीश कुमार का वोट बैंक नीतीश कुमार से नाराज लोगों को एकत्र कर नई पार्टी बनाकर असर डाल सकते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल, उपेंद्र कुशवाहा पटना में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाकर अपने लिए समर्थन जुटाने की कवायद में जुट गए हैं। इसे कुशवाहा के शक्ति प्रदर्शन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर वे अपने साथ बड़ी संख्या में नेताओं को लाने में सफल होते हैं, तो नीतीश कुमार के सामने चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे में जेडीयू के अंदर जारी घमासान के बीच पार्टी में दो फाड़ होने की आशंका जताई जा रही है।●

समाजवाद की अंतिम यात्रा

शरद यादव के निधन के बाद असली समाजवाद का अंत हो गया!

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

शरद यादव समाजवाद की अंतिम कड़ी थे उनके निधन के बाद लग रहा है की समाजवाद का किला ढह गया है। शरद यादव के सभी राजनीतिक पार्टियों में अच्छी पैठ थी और उनके संबंध सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ बड़े ही मधुर थे उन्होंने कभी भी पद के लिए निचले स्तर की राजनीति नहीं की उनके जाने के बाद समाजवाद की राजनीति में शून्य आ गया है।

शरद यादव (जन्म 1 जुलाई 1947 – 12 जनवरी 2023) भारत की एक राजनीतिक पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार प्रदेश के मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चार बार लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया था, दो बार मध्यप्रदेश के जबलपुर से सांसद चुने गये थे, एक बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए और शरद यादव संभवत: भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जो तीन राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य के लिए चुने गए थे। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे , परन्तु उनकी पार्टी द्वारा गठबंधन से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने के कारण उन्होंने संयोजक पद से त्याग पत्र दे दिया। राजनीतिक गठजोड़ के माहिर खिलाड़ी शरद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 12 जनवरी 2023 को शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। बिहार की राजनीति में शरद यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई थी। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने लोगों को उनकी ओर बांधे रखा था। समाजवाद की राजनीति के आधार पर ही शरद यादव बिहार में लोकप्रिय नेता बने थे। शरद यादव सुलझे और ईमानदार छवि के नेता थे । वे देश में पहले ऐसे सांसद थे जिन्होंने तीन राज्यों में सांसद पद संभाला था। शरद यादव अपने गृह

शरद यादव

राम मनोहर लोहिया

क्षेत्र जबलपुर लोकसभा से 1974 और 1977 में दो बार जीत दर्ज कर सांसद बने थे। तीसरी बार शरद यादव ने 1989 में उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वह बीपी सिंह की सरकार में भी मंत्री भी बने थे। हालांकि बंदायू से जीत के बाद शरद यादव का संसदीय क्षेत्र बिहार का मधेपुरा रहा जहां से वे चार बार सांसद रहे। वैसे तो वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन शरद यादव ने बिहार में एक अलग पहचान बनाई थी।

☞ **मंडल मूवमेंट :-** शरद यादव ने कहा था कमंडल का जवाब मंडल, बाद में खुद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो लिए थे। लोहिया ने पिछड़ी और अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और महिलाओं सहित विभिन्न उत्पीड़ित समूहों के उत्थान के लिए एक सामाजिक क्रांति का आह्वन किया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के तीन महीने बाद उनसे आठ साल छोटे शरद यादव का 12 जनवरी को निधन हो गया , शरद यादव के निधन के बाद असली समाजवाद का अंत हो गया । दोनों लोहियावादी राजनीतिक परंपरा से आते थे। दोनों 1990 के दशक में उत्तर भारत की राजनीति को बदलने वाले मंडल के उभार के प्रतिनिधि थे। मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी जब सोशलिस्ट पार्टियों का हिंदी भाषी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव था। वहीं शरद यादव जेपी आंदोलन से निकले थे।

☞ **कमंडल का जवाब मंडल : शरद यादव :-** लोहियावादी राजनेता और जनता परिवार का अंत अभिमन्यु की तरह हुआ। वे चुनावी राजनीति के उस चक्रव्यूह में टूट गए, जिसे कांग्रेस ने बनाया था। अब संघ परिवार ने चक्रव्यूह को अपने वैचारिक अर्थों में पुनर्गठित किया है। शरद यादव ने 1990 के दशक में सिद्धांत दिया कि कमंडल का जवाब मंडल है। 1999 तक शरद यादव खुद कमंडल के साथ जुड़े और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। यादव से पहले भी सबसे करिश्माई लोहियावादियों में से एक जॉर्ज फर्नांडिस ने एनडीए का संयोजक बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। आज लोहिया की भावना उन राजनीतिक दलों में नहीं है जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। मंडल आंदोलन एक नए ओबीसी नेतृत्व का निर्माण करने में तो सफल रहा लेकिन मुलायम और शरद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति से कोई ऐसा काउंटर नरेटिव तैयार करने में सफल नहीं हुए जो देश में बहुसंख्यकवाद के उदय को रोक सके।

जिस जनता पार्टी ने जीत हासिल की वह अलग-अलग पार्टियों और विचारधाराओं का गठबंधन थी और इसकी सफलता का कांग्रेस के खिलाफ जनता के गुस्से से बहुत कुछ लेना-देना था। जेपी की

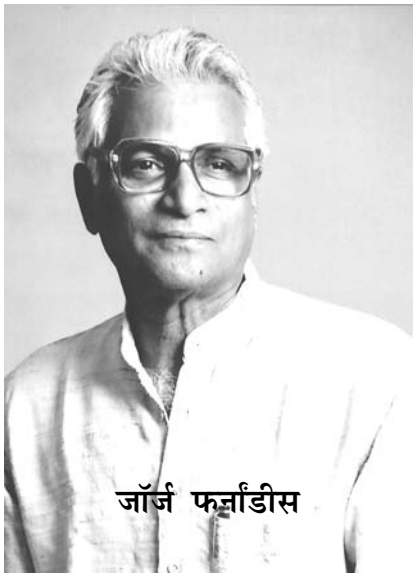
जॉर्ज फर्नांडीस

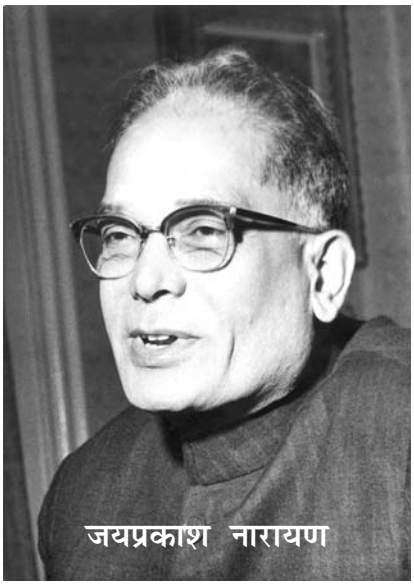
जयप्रकाश नारायण

विशाल नैतिक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया था कि उत्तर भारत में लोग जनता पार्टी के पीछे एकजुट हो जाए। आंतरिक अंतर्विरोध ों और इसके नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण जनता का प्रयोग ध्वस्त हो गया। लेकिन इससे चुनावी राजनीति में कांग्रेस का एकाधिकार खत्म हो गया। एक तरह से 1977 की जीत उस कांग्रेस विरोधी राजनीति की जीत थी, जिसे राममनोहर लोहिया ने 1950 के दशक में शुरू किया था। लोहिया का मानना था कि नेहरूवादी कांग्रेस औपनिवेशिक संस्थानों और अंग्रेजी भाषा जैसी विरासतों को जारी रखते हुए गांधी के स्वराज के आदर्शों से भटक गई है। उन्होंने पिछड़ी और अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और महिलाओं सहित विभिन्न उत्पीड़ित समूहों के उत्थान के लिए एक सामाजिक क्रांति का आह्वन किया था। एक तरह से लोहिया ने गांधी के स्वराज और सर्वोदय के आदर्शों को आंबेडकर की कट्टरपंथी जाति-विरोधी दृष्टि से जोड़ा था। आश्चर्य नहीं कि मुलायम सिंह और शरद यादव जैसे पहली पीढ़ी के नेताओं ने लोहिया को एक वैचारिक गुरु के रूप में पाया। वास्तव में मुलायम और शरद यादव जैसे नेताओं का उदय लोहिया की उस राजनीतिक दृष्टि की विजय थी, जिसमें अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को बदलने के लिए शूद्र क्रांति की कल्पना की गई थी। यदि लोहिया ने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद

मुलायम सिंह यादव

यादव और शरद यादव को वैचारिक आधार दिया, तो मंडल आंदोलन ने उन्हें यूपी और बिहार में कांग्रेस के एकाधिकार को खत्म करने के लिए लॉन्च पैड प्रदान किया।

अंतिम समय तक शरद यादव के साथ रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बिनू यादव कहते हैं कि उनका जन्म तो मध्यप्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र बिहार ही रहा है अंतिम समय में भी वह बिहार के राजनीतिक और बिहार की विकास की बात करते रहते थे, उन्हें बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों और अकिलियतो की चिंता रहती थी उन्होंने पिछड़ों, अकिलियतो और दलितों के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, जिसका प्रमाण उनके अस्थि कलश यात्रा में जनता के भारी भीड़ से लगाया जा सकता है। श्री यादव ने कहा कि पूरी यात्रा में जनमानस में शरद यादव की लोकप्रियता के कारण जनता की भारी भीड़ उमर रही थी और जनता "शरद यादव अमर रहे "के नारे लगा रहे थे। श्री यादव कहते हैं की हिंदी भाषी पट्टी में अब अकिलियतो , पिछड़ों , अति पिछड़ों के साथ दलित के एकमात्र रहनुमा श्री लालू यादव हैं जो समाजवाद का मजबूत स्तंभ है।

राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रवेश बहुत नाटकीय था। वह 1974 के अंत में जबलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे। शरद यादव उपचुनाव जीत गए थे। यह वही दौर था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस संसद पर हावी थी और विपक्ष लड़खड़ा रहा था। समाजवादी विचारक मधु लिमये लिखते हैं कि, "शरद यादव की जीत को जयप्रकाश नारायण ने खुद लोकप्रिय जीत बताया था। उन्होंने चेतावनी दी कि सफलता को किसी पार्टी या विपक्षी दलों की जीत के रूप में नहीं, बल्कि लोगों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। वह पूरे देश में जन आंदोलन को तेज करना चाहते थे।" इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी बनने, उनकी सरकार द्वारा न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रता को कम करने, संस्थाओं को निशाना बनाने से नाराज जेपी ने विपक्षी एकता और जनआंदोलन का आह्वान किया था। आपातकाल के 21 महीने बाद मार्च 1977 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार केंद्र में सत्ता खो दी। शरद यादव अपनी पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने तभी राजनीति में आने का मन बना लिया था। उन्होंने 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वह डॉ राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफी प्रेरित थे। यही वजह है कि शरद यादव सक्रिय युवा नेता के तौर पर कई आंदोलनों से जुड़े थे। बता दें कि शरद यादव को मिसा के तहत 1969-70, 1972 और 1975 में हिरासत में लिया गया था। शरद यादव ने सक्रिय राजनीति में 1974 में कदम रखा था।

समाजवाद के प्रखर नेता शरद यादव जदयू के पूर्व अध्यक्ष रहे और 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए. इसके साथ ही वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे. शरद यादव ने अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी पड़ाव में लालू यादव से हाथ मिलाया और अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय किया था. शरद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे. उन्होंने चुनौतियों को बड़े अवसर में बदला और दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर राजनीति में समाजवाद की विचारधारा

लालू प्रसाद यादव

को आगे बढ़ाया. खासकर बिहार की राजनीति में शरद यादव ने कई बार अहम भूमिका निभाई. शरद और नीतीश ने लंबे समय तक साथ में काम किया. लेकिन, बाद में कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और उनकी राहें जुदा हो गईं.

शरद यादव को प्रमुख समाजवादी नेता माना जाता था. जब 70 के दशक में जय प्रकाश नारायण ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा तो उसमें शरद यादव ने भी हिस्सा लिया. तब शरद कांग्रेस विरोधी लहर में राजनीति में ऊपर उठे और दशकों तक प्रमुख विपक्षी चेहरे के तौर पर बने रहे. उन्होंने लोकदल और जनता पार्टी के जरिए करियर को आगे बढ़ाया. हालांकि, अस्वस्थता की वजह से अंतिम कुछ वर्षों में वे हाशिये पर पहुंच गए. शरद यादव लंबे समय से गुर्दे से संबंधित समस्या से पीड़ित थे और नियमित रूप से डायलिसिस करवाते थे. बीते दिनों दिल्ली में छतरपुर स्थित आवास पर गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

☞ **27 साल की उम्र में पहली बार बने सांसद :-** शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और उन्होंने वहीं से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया. बाद में बिहार उनकी कर्मभूमि बन गया। शरद जब छात्र नेता था, तब उन्होंने 1974 में जबलपुर से लोकसभा उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया था. उस समय उनकी उम्र 27 साल थी. उन्हें जयप्रकाश नारायण

डॉ० प्रत्युष नंदन

समेत विपक्षी दलों ने अपना प्रत्याशी बनाया था. शरद की इस जीत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को मजबूती देने का काम किया था. 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और 1977 में फिर चुनाव हुए तो शरद ने दोबारा जीत हासिल की. इमरजेंसी विरोधी आंदोलन से चमके कई नेताओं में एक नाम शरद यादव का भी था. उसके बाद उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा और एक ऐसी छवि तैयार की, जिसने उन्हें पिछले पांच दशकों तक सांसद बनाए रखा.

☞ **दो बार केंद्रीय मंत्री बने शरद यादव :-** शरद यादव ने 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया. वे उससे पहले 1989 में वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री थे. इतना ही नहीं, 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद यादव को शरद का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण माना गया था. हालांकि, ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि बिहार के नेता अपने राज्य में राजनीति तौर पर हावी थे और दूसरों पर भारी पड़ रहे थे. वे बाहर से आने वाले नेताओं को नहीं जमने देना चाहते थे. आगे यही हुआ. बाद में नीतीश कुमार और शरद यादव के अलावा दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान बिहार में तीन प्रमुख समाजवादी नेता के तौर पर उभरे, जिन्होंने करिश्माई दोस्त-दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने-अपने रास्ते तैयार किए.

☞ **बिहार में लालू-राबड़ी राज को खत्म किया था :-** साल 1999 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव को बिहार में बड़ी स्वीकार्यता मिली. दरअसल, तब शरद और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू आमने-सामने थे और चुनाव में जीत शरद यादव के हिस्से में आई. नीतीश कुमार से जुड़ाव और भाजपा के साथ गठबंधन ने शरद को बिहार से 15 साल के लालू-राबड़ी राज को समाप्त करवाने में भी बड़ी सफलता दिलाई. हालांकि, माना जाता रहा है कि शरद यादव अपने खुद के बड़े आधार वाले नेता कभी नहीं रहे हैं. वे संसद पहुंचने के लिए लालू और नीतीश कुमार पर निर्भर रहे, लेकिन पॉलिटिकल वेट मिलते रहने से ऊंचाइयां छूने का सिलसिला आगे बढ़ता रहा. यही वजह रही कि एक समय वे दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति के उच्च स्तर पर पहुंचे. उन्हें मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाने में भी महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है.

☞ **इस वजह से नीतीश से नाराज हो गए थे शरद :-** नीतीश कुमार द्वारा 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला किया. हालांकि, शरद यादव साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे. 2014 की हार के बाद नीतीश और शरद के बीच खटास आना शुरू हो गई थी. नीतीश कुमार ने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए शरद के कट्टर प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया. पार्टी के फैसलों को लेकर धीरे-धीरे नीतीश और शरद यादव में अनबन बढ़ती गई. इस बीच, नीतीश कुमार ने 2017 में फिर से भाजपा के साथ हाथ मिला लिया. कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इस फैसले ने शरद यादव का धैर्य तोड़ दिया. उन्होंने विपक्षी खेमे में रहने का फैसला किया और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नाम की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया. हालांकि, ये नई पार्टी कभी उड़ान नहीं भर सकी और शरद यादव के खराब स्वास्थ्य ने उनकी सक्रिय राजनीति को लगभग समाप्त कर दिया. ऐसे में उन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दिया. तब शरद यादव ने कहा था कि दो यादव एक साथ आ रहे हैं। एक लालू यादव और दूसरे शरद

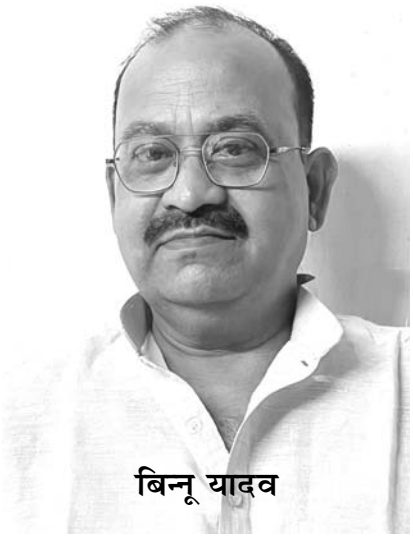
बिन्नू यादव

यादव। शरद यादव ने राजनीतिक करियर की शुरुआत एच.डी. देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ की, जबकि शरद, नीतीश और लालू को जेपी का शिष्य माना जाता है।

युवा एवं छात्र समाजवादी नेता एवं छात्र जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रत्युष नंदन ने शरद यादव के साथ एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहते हैं, कि नीतीश कुमार ने जब शरद यादव को विश्वास में लिए बिना लालू यादव से गठबंधन तोड़ दिया, तब उनको मनाने के लिए उनके आवास पर भाजपा के वरीय नेता अरुण जेटली और राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने उन्हें देश के रक्षा मंत्री के पद का ऑफर भी दिया था लेकिन उन्होंने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, इसलिए हम अपने सिद्धांत से बंधे हुए हैं और उन्होंने भाजपा से आए ऑफर को स्वीकार नहीं किया।

नीतीश कुमार की बात नहीं मानने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और नीतीश कुमार ने उन्हें भाजपा के साथ मिलकर राज्यसभा के सदस्यता से उन्हें बर्खाश्त करवा दिया। नीतीश कुमार युवा जनता दल में जब शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब नीतीश कुमार युवा जनता दल के बिहार प्रदेश के महासचिव थे। इसका अर्थ हुआ कि चेला नीतीश कुमार ने गुरू शरद यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया। ●

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूक : राज्यपाल

● अमित कुमार

महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने बिहार मानवाधिकार आयोग के 14 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीते 21 जनवरी को ऊर्जा स्टेडियम, पटना में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों को किसी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना जाता है। हमेशा और सभी जगह मिलनेवाले ये अधिकार सबके लिए समान होते हैं तथा किसी व्यक्ति को रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति या अन्य आधारों पर इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी व्यक्ति से इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। राज्यपाल ने कहा कि व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गयी तथा मनुष्य की गरिमा और अधिकारों के मामले में समानता दी गई। साथ ही, यह भी कहा गया कि उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण विकास, सामाजिक प्रगति व प्रतिष्ठा तथा जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है तथा राज्य का प्रमुख दायित्व है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 10 दिसम्बर, 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की स्थापना की गई। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा प्रदत्त दायित्वों एवं शक्तियों के आलोक में अपने स्थापना काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु बिहार मानवाधिकार आयोग सतत प्रयत्नशील है। आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में त्वरित तथा कई महत्वपूर्ण मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर भी कार्रवाई की जाती है। माह जुलाई, 2019 से एच.आर.सी. नेट पोर्टल के माध्यम से परिवादों की प्राप्ति एवं कार्रवाई की ऑनलाईन व्यवस्था शुरू होने से परिवादी ऑन लाईन परिवाद दाखिल कर सकते हैं। किसी भी केश से संबंधित सुनवाई की तिथि एवं आदेशों को ऑनलाईन देखा जा सकता है। इससे आयोग के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है एवं आम जन को भी सुविधा हुई है।

कार्यक्रम में बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिन्हा ने राज्यपाल को पौधा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने बिहार मानवाधिकार आयोग की स्मारिका का विमोचन किया तथा निबंध एवं चित्रंकन आदि से संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम को बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, न्यायमूर्ति श्री अरविन्द श्रीवास्तव एवं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री उज्ज्वल कुमार दुबे व श्री शशि शेखर शर्मा एवं सचिव श्री राजेश कुमार तथा अन्य लोग उपस्थित थे। ●

मुख्यमंत्री ने निर्मानाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का किया निरीक्षण

● अमित कुमार/त्रिलोकी नाथ प्रसाद

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 8 फरवरी को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ पर निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य में तेजी लायें और इसे सितंबर तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी इसकी सतत् निगरानी करते रहें। निर्माण कार्य हेतु पत्थर मिलने में हो रही कठिनाई के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से निर्माण एजेंसी को पत्थर उपलब्ध कराने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि बुद्ध कलश स्तूप का निर्माण कार्य भी बेहतर ढंग से और तेजी से कराएं। परिसर में अच्छे ढंग से वाटर बॉडी का भी निर्माण कराएं। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर यहां पर बाहर से और पर्यटक आएंगे। बोधगया और राजगीर आनेवाले श्रद्धालु यहां भी आएंगे। यहां पहुंचने के लिए आवागमन को भी बेहतर किया जा रहा है ताकि आसानी से और कम समय में पर्यटक यहां पर पहुंच सकें। वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, यहीं से बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला था और बाद में बौद्ध धार्म से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ने लगीं। यहां पर अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों के आने से रोजगार बढ़ेगा। परिसर के अंदर भी रास्ते का निर्माण ठीक से कराएं।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव श्रीमती बन्दना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वहां प्रदर्श योजना के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रसंगों को यहां दर्शाया जाएगा। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय, विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल, मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव श्रीमती बन्दना प्रेयसी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर सचिव श्री दीपक आनंद, तिरहुल प्रमण्डल के आयुक्त श्री गोपाल मीणा, पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह, वैशाली के जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो और वैशाली के पुलिस अधीक्षक श्री मनीष सहित अन्य अधिकारीगण एवं निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी के अधिकारी भी उपस्थित थे।●

जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी

यह जाति पर नहीं बल्कि मजदूरों पर होना चाहिए : चंद्र प्रकाश सिंह

कार्ल मार्क्स ने कामगार वर्ग या सर्वहारा वर्ग को वैसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया, जो मजदूरी के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं रखते। कामगार वर्ग का इतिहास आमतौर पर अंग्रेजी कॉमन्स की नीतियों और हॉलैंड और इंग्लैंड में कारखानों में भुगतान वाले औद्योगिक श्रमिकों की पीढ़ी के साथ शुरू हुआ माना जाता है। हमारे देश मे श्रमिकों की कार्य स्थल के पर्यावरण को सुधारने, उनके वेतन व अन्य सुविधाओं के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय श्री एम एस एस बंगाली को जाता है, जिन्होने 1875 मे एक संगठन बनाकर इस दिशा मे प्रयास किया। नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में प्रशंसित किया गया है। भारत में पहला श्रम संघ, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन उनके द्वारा शुरू किया गया था। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था, इसकी स्थापना 1918 में बी.पी. वाडिया ने वी. कल्याणसुन्दम के साथ मिल कर की थी। भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (AITUC) है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) भारत में एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है। जिसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ से जुड़ा हुआ था। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2013 में इंटक के पास 33.95 मिलियन सदस्य थे, जो इसे भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बनाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस या राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, कांग्रेस की श्रमिक शाखा है जिसका लक्ष्य देश की मजदूरों की दशा में सुधार व उनको समानता का अधिकार दिलाना है। वर्तमान समय में देश में मजदूरों की क्या स्थिति है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मजदूर को क्या-क्या मिला है और पूरे देश में खासकर बिहार में मजदूरों की दशा और दिशा बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गए हैं और लगातार वैश्विक मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्ला-चिल्ला कर भारत के अर्थव्यवस्था और विकास की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं, तो इतने बड़े अर्थव्यवस्था और विकास के जो वाहक हैं, देश के मजदूर उनके लिए देश का माहौल कैसा है? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के समाधान यात्रा में मजदूरों का समाधान हुआ है या नहीं इन तमाम प्रश्नों के साथ केवल सच के विशेष प्रतिनिधि **सागर कुमार** और **कृष्णा कुमार सिंह** ने इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष **चंद्रप्रकाश सिंह** का साक्षात्कार किया है, प्रस्तुत है इसके अंश :-

✯ वर्तमान समय में मजदूरों की क्या स्थिति है?

पूरे देश में मजदूरों के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। देश की जो ताकत है मजदूर वह विकास की गति को रफ्तार देता है जो नए-नए निर्माण और विकास के सपनों को साकार करता है, चाहे नेशनल हाईवे बनाना हो, ट्रेन की पटरी बिछाने हो, बिजली की लाइन लगानी हो, बड़े बड़े मॉल या इमारत खड़ी करनी हो, दिल्ली का पार्लियामेंट बनाना हो या कुछ और भी निर्माण करना हो, कुछ भी विकास और प्रगति का कार्य हो रहा है, उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरी तरफ खेत खलिहान में रोपनी, सोहनी का काम हो, जिस अनाज से पूरे देश का परवरिश हो रहा है उस अनाज के उत्पादन का काम हो, यह सब मजदूरों की देन है। मजदूर ही देश को दे रहे हैं लेकिन जब हम मजदूरों के माली हालात पर चर्चा करेंगें कि देश में व्यापक तौर पर परिवर्तन हुआ है उसकी अपेक्षा में मजदूरों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। आज से 50 साल पहले खेत खलिहानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और अभी

वर्तमान समय के मजदूरों कि सुविधाओं, सर्विस कंडीशन, रिटायरमेंट, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि के बारे में जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों में कुछ फर्क नजर नहीं आता है और ऊपर से मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को भी डंप कर दिया है। उसके बाद मोदी जी ने कोरोना के पहले और कोरोना के दरमियान कुल तीन श्रम काला कानून पारित कराएं परंतु उसको अभी तक लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी सभी मजदूर संगठन उस कानून का विरोध कर रहे हैं मोदी जी को डर है कि कहीं तीन कृषि काला कानून की तर्ज पर तीन मजदूर काला कानून भी वापस ना करना पड़े। इसलिए डर के कारण मोदी जी इन मजदूर काला कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इन कानूनों से केंद्र सरकार की नीति और नियत का पता चलता है। आपने हड़ताल पर रोक लगा दिया । हड़ताल का नोटिस जिस समय से दिए जाए, कानून के अनुसार वार्ता उसी समय से शुरु हो गई और जबकि व्यवहारिकता में ऐसा नहीं होता है और फिर कानून में है कि वार्ता शुरू हो गई तब फिर आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। मतलब साफ है, यह जबरदस्ती का कानून है पूरे देश में इन्होंने हायरिंग फायरिंग फ्री कर दिया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को, मजदूर को जब चाहे तब निकाल सकते हैं यह परिवर्तन आखिर कैसा परिवर्तन है।

✯ आपके कहने का मतलब है कि पिछले 8-9 सालों में ही मजदूरों की स्थिति दयनीय हुई है और इसके पहले तो मजदूरों की स्थिति काफी अच्छी थी जब देश में कांग्रेस का शासन था?

देखीए पहले यह तो था कि हम नौकरी में हैं तो हम प्रोटेक्शन फील करते थे, लेकिन आज हमारा प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया। एक नौकरी करने वाले आदमी को चाहिए क्या की नौकरी में सुरक्षा है कि नहीं, हम आखिर कब तक इसमें कार्य कर सकते हैं, कब तक इस नौकरी में हम सुरक्षित हैं और यह सुरक्षा ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं रही। कंपनी जब चाहे आप को निकाल सकती है। जांच को पूरी तरह से बंद कर दिया। कंप्लेन पर भी जांच नहीं हो पाता है । अभी के अनुसार मालिक अगर लिखकर दे दे कि उनके यहां सभी चीजें ठीक है, सभी नियम पूर्वक हैं तो वहां पर कोई जांच ही नहीं होगी चाहे उसका मजदूर या कर्मचारी कितना भी कंप्लेन करें, हल्ला करें, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

✯ एक और बड़ी समस्या देखने को मिल रही है और हम लोग लगातार इसको देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराने वाली कंपनियां मजदूरों को कर्मचारियों को उनके न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर रोजगार मुहैया कराती है और जब सैलरी लेने के लिए रिसीविंग पर मजदूर या कर्मचारी का सिग्नेचर कराना होता है तो उस पर लिखा हुआ राशि मजदूरों के हाथ में मिलने वाली राशि से दो गुना, तीन गुना होता है मतलब साफ है कि कंपनी 25 हजार रुपए से 30 हजार रूपये वाले सैलरी पर सिग्नेचर कराती है और मजदूरों को मात्र 8 हजार से 10 हजार रुपए ही देती है और अगर मजदूर इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे उसके जॉब से हाथ धोना पड़ता है। क्या कहेंगे?

अब यही तो हम लोग कह रहे हैं कि इस कंप्लेंट को जब हम लोग सरकार के पास करते हैं तो सरकार जांच नहीं करती है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने उनको कागज दिखा दिया तो सरकार उसी पर डिपेंडेंट रहती है। एक कर्मचारी को उसका नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। उसका पे स्लिप नहीं मिलता है। उसका वर्किंग आवर कितने देर का रहेगा वह नहीं पता चलता है। अब इन सभी चीजों की जांच ही नहीं होती है तो क्या पता चलेगा।

✯ इन सभी मसलों और मुद्दों पर इंटक की क्या भूमिका है?

नगर निगम और नगर पालिकाओं में काम करने वाले दैनिक मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। उनके मजदूरी का ठीक ढंग से निर्धारण नहीं होता था। उनको प्रोविडेंट फंड और स्वास्थ्य सुरक्षा ईएसआईसी नहीं मिलती थी। यह इंटक का ही काम है कि आज नगर पालिका नगर निगम में काम करने वाले दैनिक मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध है। इंटक ने लंबी लड़ाई लड़ी और 2016 में जीत मिली। यह इंटक की ही देन है। कानून तो 2011 में ही पास हो गया था परंतु हम लोगों ने लंबी लड़ाई कर इसे लागू करवाया। आप देख लीजिए जहां भी इंटक का यूनियन खड़ा है वहां पर मजदूरों की स्थिति काफी मजबूत है। उनकी नौकरी सुरक्षित है। मजदूरों के सैलरी का लगातार रिवीजन कराना, उन्हें सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराना, मृत्यु हो जाने के बाद उचित मुआवजा दिलवाना, उनके डिपेंडेंट को नौकरी दिलवाना, विधवा महिलाओं को पैसे दिलवाना यह सभी कार्य इंटक लगातार करते आ रही है।

✯ इंटक कांग्रेस समर्थित संगठन है और बिहार में कांग्रेस समर्थित

महागठबंधन की सरकार है। इस प्रकार आपका भी प्रतिनिधित्व इस सरकार में है तो आप लोग इस वर्तमान नीतीश सरकार में मजदूरों के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं?

देखिए सरकार का पक्ष अलग है और संगठन का पक्ष अलग है। कांग्रेस हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है और हम कांग्रेस के महात्मा गांधी जी के नीतियों पर चलते हैं। कांग्रेस के राज में डर नहीं था देश में आज मजदूरों में डर है। एक बात समझने वाली है कि केवल सत्ता परिवर्तन होने से या पॉलिटिकल बदलाव हो जाने से मजदूरों की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि कोई भी सरकार हो किसी की भी सरकार हो बहुत कुछ होने वाला नहीं है लेकिन वर्तमान नीतीश सरकार ने 10 लाख रोजगार का वादा किया है, जिससे कुछ तो आशा जगी है कि अब 10 लाख रोजगार मिलेगा और उनकी सोशल सिक्योरिटी भी रहेगी क्योंकि अब तक बीजेपी तो केवल रोजगार के अवसर देने की बात करती थी प्रधानमंत्री जी ने दो करोड़ स्वरोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी परंतु अब कह रहे हैं कि रोजगार थोड़ी ना कहे थे रोजगार के अवसर देने की बात कहे थे। अब इस फर्क को आप लोग समझते रहिए कि रोजगार और रोजगार के अवसर में फर्क क्या है।

✯ क्या पकौड़ा तलने को आप रोजगार नहीं मानते है?

पकौड़ा तलना, कचौड़ी बेचना, सब्जी बेचना, झाड़ू लगाना, यह सब तो काम है ही। यह सब स्वरोजगार है और सरकार को इन सब रोजगारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे रोजगार करने वाले लोगों को मदद करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि नौकरी नहीं मिल रहा है तो पकौड़ा तल लो और कचौड़ी बेच लो, यह सरकार का भाषा नहीं होना चाहिए। पकौड़ा तलने वाले बुरे थोड़ी है या कचौड़ी बेचने वाले बुरे थोड़ी है लेकिन आपका काम यह नहीं ना है कि पढ़े-लिखे शिक्षित नौजवान को कहें कि नौकरी नहीं मिल रहा है तो पकौड़े तल लो, कचौड़ी बेच लो। इसके बाद सरकार कहती है कि नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनो अब आप ही सोच लीजिए कि जब सब लोग नौकरी देने वाला हो जाएगा तो नौकरी लेने वाला क्या विदेश से आएगा?

✯ बिहार में आखिर पलायन क्यों नहीं रुक रहा है?

कोरोना के समय बिहार ही नहीं पूरी दुनिया ने बिहारी माइग्रेंट मजदूरों की स्थिति देखी है। उस समय ऑन रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश से बिहार वापस आए। ऑफ द रिकॉर्ड उससे कहीं अधिक हो सकते हैं। मोटा मोटी एक अनुमान है कि 60 लाख से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स बिहार से बाहर काम करते हैं। अगर स्वेच्छा से माइग्रेशन हुआ है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन मजबूरी में

रोजगार न मिलने के कारण, दवा न मिलने के कारण, पढ़ाई न मिलने के कारण माइग्रेशन हो रहा है तो उनमें अधिक संख्या अकुशल मजदूरों की भी है।

और ऐसा भी नहीं है कि कुशल लोग बिहार में नहीं है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए बिहार के कुशल मजदूर आपको मिलेंगे। आप देखते हैं कि कहीं भी दुर्घटना होती है, किसी फैक्ट्री में कुछ चीजें होती है, कहीं पुल-पुलिया गिर जाता है, कहीं आग लग जाता है या कहीं कोई बहुत अच्छा विकास का कार्य हो जाता है तो वहां बिहार के मजदूर आपको जरूर मिलेंगे। बिहार के लोग पंजाब को विकसित बनाएं, हरियाणा को विकसित बनाएं, दिल्ली को विकसित बनाएं, मतलब कहां नहीं गए बिहार के लोग और जहां गए वहां पर विकास किए। बिहारियों ने अपने काम के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने कौशल के बल पर, अपने ताकत के बल पर दूसरे राज्यों को समृद्ध बनाया है। यही जरूरत है बिहार को कि हमारा जो मानव बल है उसको कैसे हम बिहार के विकास में लगा सकते हैं। हमने कहा है कि माइग्रेशन पर बिहार सरकार को एक डाटा तैयार करना चाहिए । यह डाटा पंचायत स्तर पर तैयार करना चाहिए कि किस गांव के लोग किस कार्य के लिए, किस जगह पर जा रहे हैं। उसका सर्वे करिए, उसका अध्ययन करिए, अगर बिहार के लोग एग्रीकल्चर का कार्य करने के लिए पंजाब जा रहे हैं तो यह हमारे लिए सोचने की बात है कि आखिर एग्रीकल्चर की कौन सी सुविधा हमें उन्हें यहां पर देनी होगी ताकि वह बिहार में ही एग्रीकल्चर का कार्य कर सकें। यही सब काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।

✯ हमारा ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर योगी सरकार आने के बाद माइग्रेशन कम होने शुरू हुए हैं क्या आप ऐसा मानते हैं?

आज के समय में उत्तर प्रदेश माइग्रेशन में नंबर वन है दूसरे नंबर पर बिहार है। हम यूपी बिहार की तुलना इस मामले में भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया काफी बड़ा है उनके पास इंडस्ट्रियल हब है परंतु वहीं बिहार उद्योग वीहीन राज्य भी कहा जाता है और यही कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। नीतीश जी उधर रहे तब भी और इधर रहे तब भी बराबर बिहार के विशेष दर्जे की मांग इसीलिए करते हैं। यही तो तकलीफ है बिहार वासियों की।

✯ भारतीय मजदूर संघ और इंटक के विचारों और कार्यों में क्या अंतर है?

भारतीय मजदूर संघ और इंटक के विचारों में काफी असमानताएं हैं। देखिए 2009 में आजादी के लगभग 65-67 साल बाद देश में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एकजुटता बनी और मावलंकर हॉल कंस्टीटूशनल क्लब में देश के श्रमिक संगठनों की बैठक हुई। उसमें मजदूर संघ भी शामिल था। इंटक भी शामिल था। लेफ्ट के भी सभी मजदूर संगठन शामिल थे।

उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और आप कहते हैं ना कि हम कांग्रेस समर्थित संगठन है और सही में हम कांग्रेस को अपना मातृ संगठन मानते हैं और यह प्रयास भी करते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से सत्ता में आए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर ही सामाजिक सौहार्द बनेगा और देश में मजदूरों का वास्तविक विकास होगा। जो नेतृत्व का तरीका है वह कांग्रेस के पास है और भारत के लोग देख भी रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को जोड़ने का प्रयास भी किया है। हम आपको फिर से दोबारा याद कराना चाहते हैं कि उस समय 2009 में मनमोहन सरकार के रहने के बावजूद हम लोगों ने केंद्र सरकार के कुछ नीतियों के खिलाफ अर्थात अपने ही सरकार की नीतियों का विरोध किया था।

और भारतीय मजदूर संघ भी उस समय हम लोगों के साथ ही था । लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार आई, भारतीय मजदूर संघ उस एकता से बाहर निकल गई, तो यही हमारी नीति है और यही फर्क है। भारतीय मजदूर संघ का अपना अलग एजेंडा है। इनका आरएसएस का एजेंडा है। इनका एजेंडा ना मजदूरों का है, ना नौजवानों का, ना देश का, ना गरीबों का एजेंडा है। इनका अपना खुद का एजेंडा है और इनका एजेंडा क्या है वह पूरा देश जानता है। इनको अगर हमारे बराबरी में काम करना था तो हमें छोड़कर क्यों भाग गए जब 2009 में सभी श्रमिक संगठनों की एकता बनाई गई उसमें वे भी सम्मिलित थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार बनने पर तुरंत उस संगठन से भाग गए। क्यों भाग गए, बताइए जरा। यह जवाब तो उनको देना चाहिए ना क्यों भाग गए? तो इंटक से मुकाबला करना मुश्किल है। आजादी के बाद जब भी कांग्रेस की सरकार बनी तो मजदूरों से संबंधित कोई भी कानून पास होता था तो उसमें इंटेक से सलाह लेकर मजदूरों के कानून बनाए जाते थे। अभी आप बता दीजिए ना कि भारतीय मजदूर संघ से कौन सा सलाह लेकर पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं। यह लोग एक तरफ तो श्रम कानून का विरोध भी करते हैं इसके लिए अलग से आंदोलन भी करते हैं और कहते हैं कि हम लेबर कानून के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ श्रमिकों का संगठन है उसमें भी साथ नहीं देते यह तो दो तरफा है ना।

✯ क्या कांग्रेस में आप अपना भविष्य देख रहे हैं?

देश के मजदूरों का अगर भविष्य है तो वह कांग्रेस के ही सरकार में ही है। कांग्रेस के अलावे हर लोगों ने ताकत को आजमाया है। लेफ्ट ने भी कई साल शासन किया है परंतु जा कर देखिए क्या हालत है मजदूरों का। तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो कांग्रेस मजदूरों के साथ दिखाई देगी क्योंकि आप देखिए ना कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने वाली कितनी सरकारें हैं और कौन सी सरकार हैं।

✯ इंटक से इतर कांग्रेस संगठन में यह चर्चा जोरों पर है कि आज के वर्तमान स्थिति में बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास भी इतनी भीड़ और इतनी ताकत नहीं है जितनी कि चंद्रप्रकाश सिंह के पास है इस पर आप क्या कहेंगे?

यह बात हम नहीं मानते हैं। हमारे सभी बड़े नेता हमारे आदरणीय हैं सबका हम विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हैं। अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बने हैं और हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से पूर्ण ताकतवर बनेगी।

✯ आने वाले समय में आप कांग्रेस में रहेंगे?

देखिए हम तो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे । हम 1978 से कांग्रेस में हैं। इतने वर्षों में हमने एक सेकेंड के लिए भी कांग्रेस का त्याग नहीं किया है और हम तो जीवन पर्यंत कांग्रेस में ही रहेंगे हम कहीं जाने वाले नहीं है।

✯ आने वाले समय में आप विधानसभा में दिखेंगे या विधान परिषद

में दिखेंगे?

नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अपना लेबर मूवमेंट से संबंध है। मजदूरों की सेवा करना चाहते हैं। मजदूर आंदोलन को देश में बढ़ाना चाहते हैं। हमको इंटक ने और कांग्रेस ने बहुत दिया है। हमने दुनिया के कई देश में इंटक के तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि अभी 3 इंटरनेशनल यूनियन के साथ हमारा टाई अप हुआ है। इसके साथ ही आईएलओ ने काम करने के लिए चार राज्यों को सिलेक्ट किया उसमें बिहार का भी नाम है तो हमको गर्व है कि ग्लोबल जो यूनियन है हम उसका हिस्सा है और जो विश्व में मजदूरों के सबसे बड़े संगठन हैं उनको भी अच्छा लगता है कि इंटक बिहार अच्छा काम कर रही है।

✯ केंद्रीय बजट 2023 से मजदूरों को क्या मिला?

इस बजट से मजदूरों को, मजदूर जमात को कुछ मिला हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अभी ही नहीं जब से मोदी सरकार आयी है तब से बजट में मजदूरों के लिए तो हम लोग कुछ देखते ही नहीं हैं। इन लोगों के आंकड़ों के मायाजाल पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर मजदूरों के लिए कुछ किया जा सकता था। यूपीए सरकार के समय ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी के रूप में मनरेगा मिला था। परंतु अब की सरकार उसमें भी कटौती करते जा रही है। जो सबसे लोवेस्ट और सबसे हार्ड वर्किंग है उस पर तो सरकार का ध्यान नहीं है। ना ही बजट में ओल्ड पेंशन बहाल करने की बात कही गई है, ना हीं बजट में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात की गई है, ना ही सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, ना ही पी एफ सीलिंग के बारे में बात की गई है और ना ही ईएसआईसी के बारे में बात की गई। पूरे मजदूर जमात को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। सरकार ने भी इस श्रम पोर्टल के माध्यम से यह अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 38 करोड मजदूर हैं। तो देश में इतने बड़े समुदाय के लिए बजट में कुछ नहीं होना दुर्भाग्य है। आखिर ये बजट यह लोग किन के लिए लाए हैं। अगर कुछ भी इन मजदूरों के लिए सरकार ने बजट में लाया है तो हमें बता दें? श्रम पोर्टल पर जो निबंधित मजदूर है उनके बारे में भी इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है ,ना ही उनके सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है ,ना ही उनको किसी योजना से जोड़ने के बारे में कहा गया है। 2008 में सामाजिक सुरक्षा कानून बना हुआ है उसमें कितना फंड है, कांग्रेस शासन के द्वारा अपने शुरुआती दिनों में एक फंड डाला गया अब तो मोदी सरकार उसके बारे में चर्चा तक नहीं करती है। मजदूरों के लिए क्या किया है कोई बता दे?

✯ बिहार में हो रहे जाति जनगणना से मजदूरों को क्या कोई फायदा है?

देखिए जातीय जनगणना और मजदूर यह दोनों अलग-अलग विषय है परंतु अच्छी नियत से अगर कोई काम हो रहा है तो उस में व्यवधान उत्पन्न करना तो ठीक बात नहीं है। होने दीजिए इसमें हर्ज ही क्या है? हो सकता है उसे मजदूरों का वेतन बढ़ेगा, ज्यादा काम मिलेगा, उनको योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जो कमजोर है उनको उठाया जाएगा, तो होने दीजिए इस में दिक्कत क्या है?

✯ पिछले 70 सालों से मजदूरों के नेता मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन क्या कारण है कि मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेता की लाइफस्टाइल, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेता की ग्रोथ, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेता की पॉलिटिकल पकड़ और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेताकी आर्थिक व्यवस्था और दूसरी तरफ जिन मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है वह मजदूरों की स्थिति उनकी लाइफस्टाइल उनकी पॉलिटिकल पकड़, उनकी आर्थिक व्यवस्था में इतना अंतर क्यों है? आखिर क्यों नेता अमीर होते जा रहे हैं और मजदूर गरीब?

देखिए मोदी जी चाय बेचते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो कितना चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। कोई भी नेता किसी ऊंचाई पर आकर चला जाता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारी जनता भी उसी ऊंचाई पर चली जाए। इसका कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। जो भी आदमी काम कर रहा है तो देखना होगा कि उसने देश के लिए क्या किया है। जनता के लिए क्या किया है। मजदूरों का नेता है तो मजदूरों के लिए क्या किया है। मजदूरों को उस नेता से क्या-क्या फायदे हुए हैं।

मजदूरों के लिए नेता कितना लड़ाई लड़ा है। मजदूर आंदोलन को कभी भी पॉलीटिकल सपोर्ट मिला ही नहीं इस देश में। कांग्रेस के शासनकाल में इंटक ने मजदूरों के कानून बनवाएं परंतु पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब क्या है? आप देखिए कि लेबर लीडर या मजदूर नेता के तौर पर संसद में और विधानसभाओं में कितने नेताओं का प्रतिनिधित्व है। शिक्षक के प्रतिनिधि रहते हैं, डॉक्टरों के प्रतिनिधि रहते हैं, खेल के प्रतिनिधि रहते हैं, तमाम लोगों के प्रतिनिधि रहते हैं लेकिन उन मजदूरों के प्रतिनिधि के तौर पर संसद में बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। लेबर मूवमेंट का रेपुटेशन इस देश में लोगों ने ठीक नहीं होने दिया। मजदूर जब हड़ताल करते हैं अपनी मांगों को लेकर, काम बंद करते हैं तो जनता कहती है कि यह लोग कहां से आ गया क्या कर रहा है। बैंक के लोग हड़ताल करें, रेल कर्मचारी हड़ताल करें, मनरेगा के मजदूर हड़ताल करें, दिहाड़ी मजदूर हड़ताल करें, नगर निगम, नगर परिषद के मजदूर हड़ताल करें, खेत के मजदूर हड़ताल करें तो लोगों को परेशानी होती है। खेती के मजदूरों को तो नक्सल तक का दर्जा दे दिया गया। देखिए यह बात सही है कि मजदूरों को लेकर इस देश में भी पॉलिटिकल एप्रोच बन नहीं पाया है। आप बता दीजिए कि देश में अनुमानतः 38 करोड़ मजदूर है और देश की संसद में उनके लिए किसी एक मुद्दे पर बहस हुआ हो, संसद ना चला हो। जो 5-10 मजदूर नेता काम कर रहा है तो आप चाहते हैं कि वह भी काम ना करें तो देश में मजदूरों को देखेगा कौन? उनके लिए लड़ेगा कौन? कोई है मजदूरों को देखने वाला? आजादी के इतने दिनों बाद एग्रीकल्चर लेबर का सोशल सिक्योरिटी के साथ क्या कोई कनेक्शन है। कुछ है ही नहीं, काम करिए देश का पेट पालिए और अपने भरोसे रहिए। अभी बिहार में बात हो रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यह जात के नाम पर क्यों हो रहा है यह मजदूर के नाम पर क्यों नहीं हो रहा है? मजदूर से ज्यादा किसकी संख्या है? मजदूर की संख्या के हिसाब से बजट क्यों नहीं पास हो सकता है? तो कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है इस देश में जिसको लोग उजागर नहीं करता है। अमीरी गरीबी की बात होती है मजदूरों के लिए हर चीज न्यूनतम की बात की गई है। न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम बोनस, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए न्यूनतम मुनाफा कमाने का सीलिंग है क्या? मजदूर के लिए तो सीलिंग है कि आप कितना भी कमाएंगे तो 20% से अधिक बोनस नहीं मिलेगा। उनके ग्रेच्युटी में भी सीलिंग है लेकिन उद्योगपति के लिए ऐसा नहीं है कि वह एक साल में कितना मुनाफा कमाएंगे। लेबर रिफॉर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया लेकिन फिर पॉलीटिकल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टर रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे कमजोर

आपको मिल गया मजदूर तो उसी का रिफॉर्म करने चल दिए। हर जिले में नया जमीदार बैठ गया है डीएम उसका रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका कहना है कि रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस। अर्थात् बिजनेस को आसान बनाने के लिए लेबर रिफॉर्म हो रहा है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात मजदूरों के लिए होनी चाहिए। हम देश के मजदूर जो दे रहे हैं वह हमारा कंट्रीब्यूशन है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बजट में हो रहा है, उसमे मजदूर कहीं नहीं है। यही मुख्य लड़ाई है। धन्यवाद!

देश के सबसे बड़े मजदूरों के संगठन इंटक के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देश विदेशों में मजदूरों के नेता के नाम से प्रचलित और बिहार में जमीनी नेता के तौर पर काम करने वाले मजदूर नेता चंद्रप्रकाश सिंह से तमाम कई मुद्दों पर बातचीत हुई । जिस पर उन्होंने खुलकर, बेबाकी भरे लफ्जों में अपनी बातें रखीं । उनके कार्यकाल में व उनके कार्यकाल से पहले भी मजदूरों के लिए इंटक ने जो कार्य किए हैं और जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा कर बताया कि देश में मजदूरों की स्थिति अभी ठीक नहीं है देश में मजदूर डरे हुए हैं। उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकारों ने छीन ली है। और केंद्रीय बजट में भी उनके लिए कुछ नहीं है। इंटक भले ही कांग्रेस समर्थित मजदूर संगठन है लेकिन यह बात सही है कि जब जब मजदूरों के हितों की बात आई है इंटक ने अपने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला है और मजदूर नीतियों पर उनका विरोध व उनका घेराव भी किया है। चंद्रप्रकाश सिंह कांग्रेस के काफी लंबे समय से नेता रहे हैं। साक्षात्कार के दौरान तो उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में जाने से साफ मना कर दिया परंतु हमारे सवालों के जवाब देने के क्रम में उन्होंने बताया कि विधानसभा/विधान परिषद और देश के संसद में मजदूर नेता के प्रतिनिधि के तौर पर कोई दिखता नहीं है तो इस अंदाज पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश सिंह भी देश की लोकतंत्र के मंदिर में जाकर मजदूरों के हक की आवाज उठाना चाहते हैं , उनके पास मजदूरों और मजदूरों से जुड़े हुए जो अनुभव है उसका उपयोग विधानमंडल और सदनों में जाकर मजदूरों के हितों में करना चाहते हैं जिसके लिए शायद वह बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि बिहार कांग्रेस संगठन में वैसे दमखम वाले , अनुभवी, ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले कट्टर कांग्रेसी और अपने नाम पर भीड़ जुटा लेने वाले गिने चुने नेताओं में चंद्रप्रकाश सिंह का नाम काफी प्रमुखता से आता है परंतु देखने वाली बात यह है कि जहां भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए राहुल गांधी बिहार तक नहीं आ पाते हैं और यहां के नेताओं में आपसी सामंजस्य की भी कमी दिखती है तो ऐसे में बिहार कांग्रेस से किस प्रकार अपने आप को अखिलेश प्रसाद सिंह (नवनिर्वाचित अध्यक्ष)के नेतृत्व में संयमित और संगठित होकर, पुनः पुराने रंग में रंगकर बिहार में कांग्रेस को फिर से स्थापित कर पाती है। ●

नालंदा खुला विश्वविद्यालय का पंद्रहवाँ दीक्षान्त समारोह संपन्न

बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है : राज्यपाल

● रीता सिंह

ज्ञान की भूमि बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है तथा यहाँ के नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विश्व भर से विद्यार्थी विद्या ग्रहण के लिए आते थे। बिहार की इस प्रतिभा सम्पन्न धरती को भगवान बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट आदि अनेक महापुरूषों और विद्वानों ने गौरवान्वित किया है। यह बातें महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने बापू सभागार, पटना में आयोजित नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए कही। समारोह में राज्यपाल को नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० के.सी. सिन्हा ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह् भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को उपाधि पत्र एवं स्वर्ण पदक प्रदान किया तथा उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि दीक्षान्त समारोह सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक यादगार क्षण के रूप में आता है और इस अवसर पर उपाधि -पत्र प्राप्त करने की महती इच्छा हरेक विद्यार्थी की होती है। वास्तव में दीक्षान्त पढ़ाई का अन्त नहीं है, बल्कि सतत शैक्षणिक जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे अपना लक्ष्य महान रखें, अपनी ऊर्जा पर विश्वास करें और हार नहीं मानें, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे अपने उच्च नैतिक मूल्यों और प्राप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बदौलत राष्ट्र के विकास एवं मानवता के कल्याण में सशक्त एवं सार्थक भूमिका निभाएँगे। राज्यपाल ने कहा कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में अंकपत्र, मूल प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय परित्याग पत्र आदि मांग के दिन ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों की कर्त्तव्यनिष्ठा व विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। मुझे बहुत खुशी है कि आज नालन्दा खुला विश्वविद्यालय ने अपने 15वें दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया है। सभी विद्यार्थियों के जीवन में यह एक यादगार क्षण के रूप में आता है और यह याद दिलाकर जाता है कि अब आप स्नातक या उच्च उपाधि धारक हो गये हैं।

दीक्षान्त वास्तव में पढ़ाई का अन्त नहीं है, बल्कि सतत् शैक्षणिक जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। बिहार की यह धरती प्रतिभा की धनी है। आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे अनेक विद्वानों ने इस धरती पर जन्म लिया है, जिनसे यह क्षेत्र गौरवान्वित रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य महान रखिए, अपनी ऊर्जा पर विश्वास रखिए और हार मत मानिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको गर्व होना चाहिए कि आप बिहार के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय से उपाधि ले रहे हैं जहाँ कदाचारमुक्त परीक्षा संचालित होती है। इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि अंकपत्र, मूल प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय परित्याग पत्र आदि मांग के दिन ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तीव्र कार्य सम्पादन का यह विश्वविद्यालय परिचायक है। इस अवसर पर मैं विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने उच्च नैतिक मूल्यों और प्राप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बदौलत राष्ट्र-निर्माण में सशक्त और सार्थक भूमिका निभाएँगे। नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं उनके नेतृत्व में कार्यरत सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी को साधुवाद/आशीर्वाद देता हूँ और यह कामना करता हूँ कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ता रहे।

वही कुलपति प्रो. के.सी. सिन्हा ने कहा कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के लिए अपार हर्ष का विषय है कि हम आज 15वें दीक्षान्त समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2020 (स्नातक सत्र 201-2020 तथा स्नातकोत्तर सत्र 2018-2020) एवं वर्ष 2021 (स्नातक सत्र 2018-2021 तथा स्नातकोत्तर सत्र 2019-2021) की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जायेगी। दोनों वर्षों की परीक्षाओं में कुल 23,635 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 18,954 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन उत्तीर्ण विद्यार्थियों में लगभग 44 प्रतिशत

छात्राएँ हैं, लगभग 5000 विद्यार्थी आज उपस्थित हैं, जो इस यादगार अवसर पर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपाधि ग्रहण करेंगे। वे उत्तीर्ण विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों से आज उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें भी आज की तिथि से ही उपाधि दी जायेगी। हमारे लिए बड़े ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है कि आज के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता, महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति महोदय कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके आशीर्वचनों से विश्वविद्यालय, शिक्षकों एवं उपस्थित विद्यार्थियों को विकास की नई दिशा एवं दशा का ज्ञान हो सकेगा। वर्तमान में नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में 106 पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं, इनमें अनेक पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी, व्यावसायिक एवं कौशल विकास से सम्बन्धित है। ये सभी पाठ्यक्रम 12 विद्यापीठों के अन्तर्गत चलाये जाते हैं। आज विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग एक लाख है। अगले सत्र 2023-24 में कौशल विकास के अतिरिक्त कई अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना है। अत्यन्त कम लागत पर गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करना न केवल हमारी विशेषता है, बल्कि प्रतिबद्धता भी है। इसका प्रमाण है कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त कर सके हैं। हमारे विद्यार्थी बैंकंग सेवा, सूचना तकनीकी, मीडिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। कुलाधिपति महोदय, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय राज्य सरकार का एक मात्र विश्वविद्यालय है, जिसे राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। फिर भी, यह विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक संसाधनों से लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर रहा है। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ने की सुविधा प्रदान

करने के लिए अपने स्वाधिगम सामग्री को पूर्णतया डिजिटल बनाने तथा उसे देश के अन्य पुस्तकालयों से जोड़ने की दिशा में काफी प्रगति हासिल किया है। विश्वविद्यालय के पास 350 से भी अधिक कम्प्यूटर्स का एक अत्यन्त विकसित कम्प्यूटर लैब है। बिहार राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के मिशन को नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया है। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा चिन्हित निम्न सकल नामांकन अनुपात वाले अतिपिछडे प्रखण्डों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की, जिसके अन्तर्गत 268 अध्ययन केन्द्र संचालित है, जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवार अपने बच्चों को बिना कॉलेज या विश्वविद्यालय भेजे भी उच्चस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारपरक एवं कौशल विकास हेतु नजदीक के अध्ययन केन्द्रों में नामांकन करा सकते हैं। नालन्दा खुला विश्वविद्यालय में महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा महिला साक्षरता और सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारे इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों में से लगभग 50 प्रतिशत छात्राएँ हैं और इस दीक्षान्त समारोह में कुल 47 स्वर्ण पदकों में से 38 यानी 80 प्रतिशत से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली नियमित वर्ष में ही उत्तीर्ण महिला विद्यार्थी को अलग से स्वर्ण पदक दिया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्वर्ण पदकों में से 09 स्वर्ण पदक ऐसे हैं, जिन्हें शिक्षा जगत में रूचि रखने वाले महानुभावों ने एक-एक लाख रूपयों का अनुदान देकर अपने अथवा अपनी संस्था के नाम में स्थापित किया है। ऐसे दानदाता (Endowment) या उनके प्रतिनिधि आज के इस समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। अतः उन्हीं के कर कमलों के द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उनके द्वारा स्थापित स्वर्ण पदक को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। आप सबों के सहयोग के लिए विश्वविद्यालय परिवार आभारी है। इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 15वीं दीक्षान्त समारोह के आयोजन के गत सप्ताह पूर्व, दो दानदाताओं, यथा, सुलभ इंटरनेशनल, पटना द्वारा दो लाख एवं डा. (मेजर) बलबीर सिंह भसीन के द्वारा चार लाख रूपयों का आर्थिक सहयोग पूर्व की प्रदत्त राशि एक लाख रूपया के अतिरिक्त किया गया

महामहिम राज्यपाल फागु चौहान जी को भेंट स्वरूप रामायण देती रीता सिंह

है, जिससे सीधे-सीधे सम्बन्धित विष्य के छात्र लाभान्वित होंगे।

''पावका नः सरस्वती'' नालन्दा खुला विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह् है। इसे ऋग्वेद से लिया गया है और इसका अर्थ स्थूल रूप से यह होता है कि सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी माँ **''सरस्वती हमें पवित्र करें''**, अर्थात् हमें ज्ञान एवं विद्या से भर दें। अतः हमारी यह प्रार्थना होगी कि हमारे विद्यार्थियों पर भी माँ सरस्वती की ऐसी ही महती कृपा बनी रहे।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था-

''अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा।''

''इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी हैं।''

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अपने राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत समाज के वैसे सदस्यों को भी जो दुर्भाग्यवा जेल में सजा काट रहे हैं, पढ़ने के लिए भी यह विश्वविद्यालय प्रेरित करता है तथा समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। ऐसे विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय कोई शुल्क नहीं लेता तथा सभी सुविधाएँ समान्य विद्यार्थी के अनुरूप ही प्रदान करता है। उत्तीर्णोपरान्त उन्हें उपाधि भी प्रदान की जाती है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था-

''मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं, जब वो केन्द्रित होती हैं, चमक उठती हैं।''

''जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।''

महानुभावों, अभी तक यह विश्वविद्यालय, बिस्कोमान भवन अर्थात् कैम्प मुख्यालय से चल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा नालन्दा के बड़गाँव में भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, नालन्दा में स्थानान्तरित हो जायेगा। इसके लिए मैं राज्य सरकार को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अब मैं अपने विशिष्ट अतिथिगण, आमंत्रित मेहमान और प्यारे विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए उपाधि पत्र अधिकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं माननीय राज्यपाल तथा बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे 15वें दीक्षान्त मारोह में उपस्थित होने की कृपा की। आपके आशीर्वचनों से हमारे विद्यार्थी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मैं विनम्र सलाह देता हूँ कि वे कार्यक्रम के अन्त तक अपनी जगह पर शान्तिपूर्ण बैठे रहें तथा निदेशानुसार उपाधि अधिकरण कार्यक्रम में सहयोग करें। इससे आपकी ही प्रशंसा होगी। अन्त में मैं एक बार पुनः सभी शुभकामनाएँ देता हूँ।

दीक्षान्त समारोह को बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉ० चन्द्रशेखर एवं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पूर्व कुलपति प्रो० ए.के. बक्शी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल. चोंग्थू, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० के. सी. सिन्हा, प्रतिकुलपति प्रो० संजय कुमार, कुलसचिव, डॉ० हबीबुर्र रहमान एवं डॉ० नीलम कुमारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ●

प्रतिदिन दो घंटे लोगों की सुननी होगी फरियाद : डीजीपी

● रीता सिंह

बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब पुलिस को लोगों की फरियाद को सुनने के लिए रोजाना दो घंटे का समय देना होगा। सिर्फ छुट्टी वाले दिन को छोड़कर बिहार पुलिस आम जनता की समस्याओं को सुनेगी और तुरंत उसका समाधान भी करेगी।

दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय सहित सभी जिले रेंज के डीआईजी, आईजी और एसपी को हर दिन दो घंटे आम लोगों की फरियाद सुनना होगा। अब कोई भी व्यक्ति किसी दिन भी अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने उनके ऑफिस पहुंच सकता है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक पुलिस के अधिकारी अपने ऑफिस में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो भी शिकायतकर्ता अधिकारियों के ऑफिस में पहुंचेगा, उनसे मिलना होगा और उनकी समस्याओं को सुनना होगा। राज्य के नए डीजीपी के अनुसार हर दिन यह देखने को मिल रहा था कि लोग बड़ी संख्या में अपनी शिकायतों को लेकर पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। बता दें कि पहले से पुलिस मुख्यालय में हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को जन सुनवाई की जाती थी। इस एक दिन की जन

सुनवाई से आम जनता संतुष्ट नहीं थी। वहीं पुलिस मुख्यालय में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही था। इसे देखते हुए अब रोजाना लोगों की समस्या की सुनवाई के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ●

साम्प्रदायिक सौहार्द का सांस्कृतिक केन्द्र बनेगा कबीर मठ फतुहां

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आचार्य गद्दी कबीर मठ फतुहा बिहार का सार्वजनिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित होने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और इसका सम्पूर्ण श्रेय जाता है यहाँ के प्रबंधक, न्यासधारी महंथ रह चुके वर्तमान में मठ के संरक्षक महंथ ब्रजेश मुनि को संचित और प्रारब्ध कर्मानुसार क्रियमान जीवन में कबीरपंथी परिवार में जन्म ग्रहण कर जन्मजात कबीरपंथी संस्कार के साथ पले बढ़े ब्रजेश मुनि ने अपने मोहनपुर दियारा राघोपुर स्थित अपने जन्म स्थान को कबीर चौरा धाम नाम देकर स्वयं कबीरपंथी मठों का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। प्रातः स्नानादि पश्चात् बीजक पाठ, वाणी पाठ आदि की आचार संहिता को आत्मसात किये हुए साखी, रमैनी, दोहे आदि का वाचन और और सत्संग की योग्यता विरासत में प्राप्त हुआ। इसलिए कबीर मठ के माध्यम से स्वयं को समाज से जोड़ने में समर्पित हो गये ब्रजेश मुनि।

प्रबंधक के रूप में कबीर मठ फतुहा में मुनि जी ने सांसदों, केन्द्रीय मंत्रियों से सम्पर्क साधा, उनसे मिलकर मठ की महत्ता के बारे में बताया और इस मठ को सिक्ख सम्प्रदाय का भी तीर्थ बताया जहाँ 1506 ई० में गुरूनानक देव जी का आगमन और संत समागम हुआ था। उनके द्वारा कुआँ खनवाया गया था जो आज भी नानक कुओं के रूप में सिक्ख श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय है। प्रबंधक रहते ब्रजेश मुनि ने तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी को कबीर मठ फतुहा में आमंत्रित किया और मठ के विकास के लिए उन सबसे सहयोग का अनुरोध किया। उनके सांसद निधि से कबीरमठ

फतुहा में संत निवास बना। पर्यटन विभाग बिहार सरकार से कबीरमठ फतुहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 3.84 करोड़ (तीन करोड़ चौरासी लाख) रूपये स्वीकृत करवाये। उसकी प्रथम किस्त में प्राप्त राशि से सभागार का निर्माण हुआ। कबीरायतन आई हास्पीटल भी जन स्वास्थ्य के हित में खोला गया। हॉस्पीटल में सेवा कार्य भी आरंभ हुआ। प्रबंधक पद से हटने के बाद वह सेवा बन्द हो गयी। 2020 में जब न्यासधारी महंथ के रूप में कबीरमठ फतुहा में कार्यभार संभाला। तब मठ की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की। बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा बन्धक ली गयी मठ की जमीन विवाद को मठ की सम्पत्ति पर निगम का अवैध कब्जा बताकर उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। कबीर मठ की शाखा मठ कृष्णाटोली ब्रह्मपुर मुजफ्फरपुर की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण में वाद दायर किया। मठ के हित में मठ से बाहर ऐसे कार्यों के साथ साथ ब्रजेश मुनि ने मठ के अन्दर सेवा पूजा, राग भोग, उत्सव, समैया, सत्संग, भजन, भंडारा आदि का आयोजन भी आरंभ किया।

संरक्षक रूप में 28 से 30 जून तक कबीर मठ फतुहा में पहली बार सद्गुरू कबीर जयन्ती समारोह का आयोजन त्रिदिवसीय साम्प्रदायिक सौहार्द मेला के रूप आयोजित हुआ। इस मेला को राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री द्वारा छः लाख पचास हजार रूपये की स्वीकृति दिलवाने में सफलता प्राप्त की। उक्त मेला में राज्य के उपमुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, तख्त हरिमंदिर साहिब

गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रधान महासचिव सहित विधायक, सांसद एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर कबीर मठ में सुविधासम्पन्न कबीर वाटिका के निर्माण की घोषणा की गयी। तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रधान महासचिव अवतार सिंह हीत ने नानक कबीर मिलन स्थल रूप में इसे पटना साहिब में सिक्ख का आठवाँ दर्शनीय तीर्थ घोषित किया और यहाँ भव्य गुरूद्वारा, सुविधासम्पन्न धर्मशाला बनाने और बाग लगाने का वचन दिया। इस त्रिदिवसीय आयोजन की सफलता से उत्साहित होकर बजेश मुनि ने कबीर मठ फतुहा में पहली बार सात दिवसीय कबीर कथा का आयोजन किया। जिसकी चर्चा देश विदेश तक हुई। मठ से लोगों को जोड़ने के लिए कबीर मठ फतुहा में रविवारीय सत्संग का आयोजन आरंभ किया गया जो नियमित रूप से प्रत्येक रविवार को आयोजित होने लगा है। फतुहा के स्थानीय नागरिक के अनुरोध पर कबीर मठ में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया। बजेश मुनि जी के सत्प्रयास से कबीर मठ फतुहा से आम जनता जुड़ने लगी है और लोगों में आशा और विश्वास जगा है कि फतुहा के लोगों को निकट भविष्य में विकसित कबीर मठ शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में प्राप्त होगा और सार्वजनिक न्यास रूप में निबंधित यह गौरवशाली कबीर मठ जनोपयोगी साबित होगा। पिछले दिनों 21 से 23 जनवारी तक त्रिदिवसीय सद्गुरु कबीर महापरिनिर्वाण दिवस एवं गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव सांस्कृतिक मेला के रूप में आयोजित किया। इस सांस्कृतिक मेला में गुरूग्रंथ साहिब का अखण्ड पाठ, स्कूली बच्चों के बीच कबड्डी, दौर आदि प्रतियोगिता तथा अन्तर्राज्यीय कुश्ती का आयोजन किया जिसमें कबीर मठ फतुहा में हरियाणा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के पहलवानों ने भाग लिया। ब्रजेश मुनि के इस आयोजन से कबीर मठ फतुहां के विकास की नयी आशा जगी जब मुख्य समारोह में पधारे केन्द्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 3.84 करोड (तीन करोड़ चौरासी लाख) कबीर मठ में कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान, सभागार, पुस्तकालय सह वाचनालय, संग्रहालय आदि निर्माण के लिए केन्द्र सरकार स्तर से उपलब्ध कराने की घोषणा की।

केन्द्रीय मंत्री की इस घोषणा से समारोह में आये हजारों नागरिकों ने कबीर मठ फतुहा में सार्वजनिक हित के साधन विकसित किये जाने के लिए केन्द्रीय मंत्र की घोषणा से फतुहां के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ब्रजेश मुनि का कहना है कि वे मठ के विकास के साथ साथ मठ की अतिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका अधिकाधिक उपयोग राज्यहित और जनहित में करना हमारा ध्येय है। ब्रजेश मुनि ने कहा कि मैं मठ के विकास के हित में और सार्वजनिक हित में मठ की उपयोगिता के बारे में सोचता हूँ और उसके लिए काम करता हूँ। न्यास समिति का सहयोग नहीं मिलने के कारण मठ के विकास कार्य में बाधा उपस्थित हो रही है। यहाँ साधू संतों की सेवा मंदिर में सेवा पूजा, राग भोग की व्यवस्था भी फिलहाल स्वयं कर रहे हैं। फतुहा के अलावे ब्रजेश मुनि ने धर्माचार्य जागू गद्दी कबीर मठ बिदुपुर की शाखा मठ सोनामा दीसरगंज पटना के न्यासधारी महंथ के रूप में वहाँ की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर मठ में भवन निर्माण कराया, गो-सेवा, साधू सेवा आदि की व्यवस्था नियमित करने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ भी साधू सेवा नियमित रूप से हो रहा है। उपेक्षित कबीरपंथी आश्रम मीठापुर के न्यासधारी महथ के रूप में ब्रजेश मुनि ने इस मठ को अतिक्रमण मुक्त करा कर यहाँ अभिनव प्रयोग कर कबीरपंथी श्रद्धालुओं के साथ साथ साई भक्तों को जोड़ा और देश का पहला कबीर साई मन्दिर जन सहयोग से बनवाया। जहाँ एक टूटी झोंपड़ी थी वहाँ आज चार मंजिला भवन जन सहयोग से बनावा दिया। स्थानीय निवासियों के लिए इस स्थान को आध्यात्मिक आस्था का केन्द्र के रूप में विकसित किया। यहाँ सप्ताह में गुरुवार एवं शनिवार को भजन, सत्संग एवं भंडारा का नियमित आयोजन आरंभ किया और आम जनता को इस आश्रम में जोड़ने से सफलता प्राप्त किया। यहाँ जन स्वास्थ्य के हित में कबीर साई डेन्टल हास्पीटल भी विकसित किया जहाँ दंत चिकित्सा सेवा कार्य भी आरंभ किया गया है। इन सब कार्यो के अतिरिक्त सद्गुरु कबीर के विरासतों को जन जन तक पहुँचाने एवं जन हित में विकास कार्यों का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से ब्रजेश मुनि ने सदगुरू कबीर मिशन ट्रस्ट की स्थापना की है। इनका कहना है कि जन्म स्थान पर कबीर चौरा धाम सहित पटना के कबीरपंथी आश्रम, सोनामा कबीर मठ के महंथ के रूप में मनोनुकूल विकास में सफलता से उत्साहित होकर कबीर मठ, फतुहां को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और इसे साम्प्रदायिक सौहार्द का विशिष्ट आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर भगीरथ प्रयास करने में लगा हूँ। किन्तु इतना कुछ करने के बावजूद न तो न्यास पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का सहयोग मिल रहा है न ही धार्मिक न्यास बोर्ड मठों के हित में मेरे योगदान का मूल्यांकन कर रही है। बावजूद इसके मुझे विश्वास है कि सद्गुरु की कृपा और जनता जनार्दन के समर्थन और सहयोग से अवश्य ही अपने मठ को विकसित करने के लक्ष्य को पूरा करने में अवश्य ही सफलता मिलेगी।●

साहित्य और संस्कृति से ही किसी समाज की पहचान : प्रेम रंजन पटेल

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा के साहित्य सांस्कृति संस्था साहित्य परिषद के तत्वाधान में पटना से प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका केवल सच भारत रत्न विशेषांक का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। फतुहा के गोविंद पुर स्थिति मां तारा उत्सव पैलेस में आयोजित इस सारस्वत उक्त समारोह में उक्त विशेषांक के बहाने हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामजतन यादव ने कहा कि समाज का शैक्षिक विकास साहित्यिक के प्रचार-प्रसार पर ही निर्भर होता है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को मुद्रित साहित्य से जोड़ने का उप कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सच भारत रत्न विशेषांक पठनीय और संग्रहणीय है। समारोह के अध्यक्ष तथा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी कहा कि साहित्य और संस्कृति समाज की बौद्धिक समृद्धि का परिचायक है। सिर्फ आर्थिक नहीं हमें अपने समाज को साहित्यिक तथा सांस्कृतिक ऊंचाई के अध्ययन की परंपरा को समृद्ध करने पर जोर दिया। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव ने बढ़ते तकनीकी के साथ साहित्य के महत्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे ने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा छोटी-छोटी गोष्ठियों के माध्यम से पढ़ने की परंपरा पर बल दिया। केवल सच के प्रतिनिधि डॉ लक्ष्मी नारायण पटेल, अनिल कुमार शर्मा कार्यक्रम के विशेष प्रतिनिधि शिशुपाल यादव आदि ने अपने विचार रखे कार्यक्रम का संचालन भास्कर लाल पटवा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विमल कुमार, केशव कांत ,अरविंद यादव, अरुण झा, सत्येंद्र पासवान, शैलेश कुमार गुप्ता, अरविंद यादव, रंजीत शाह, अरुण कुमार झा ,उदय तिवारी, शोभा पटेल, पिंकी साहू ,रूबी देवी, अनामिका पांडे, रामचंद्र प्रसाद, पूजा कुमारी, आशीष कुमार अंकुश कुमार, रेखा शर्मा आदि मौजूद थे। ●

चार भ्रष्ट लोक सेवकों पर मुकदमें, सजा सार्वजनिक नहीं

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार में लोक सेवकों की मौज है,ऐसे लोग सेवकों को सजा और संपत्ति जब्ती के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। ऐसे 34 लोकसेवक है जिस पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं इनमें आईएएस ,आईपीएस बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर से लेकर इंजीनियर तक शामिल है। कई पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित का मुकदमा विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज कर रखा है तो कई लोग सेवक रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचे गए तथा उन पर मुकदमा भी हुआ। ये मुकदमे 2010 से लेकर 2022 (अक्टूबर) के बीच हुए हैं। लोक सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचना के एवज में निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मांगें गए सवालों के जवाब में निगरानी विभाग ने कई सूचनाएं सार्वजनिक करने से इनकार किया है। कितने भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जप्त की गई कितने की सजा, ऐसे कितने अफसर वर्तमान में कहां और किन पदों पर तैनात हैं इसकी सूचना नहीं दी गई जो सूचना दी गई वह आधी अधूरी है। रिश्वत देने वाले लोक सेवकों की सूची लंबी है। निगरानी विभाग में रिश्वत लेते पकड़े गए मात्र दो का ही जानकारी दी गई। भ्रष्ट लोक सेवकों के नाम पर दर्ज मुकदमा। विशेष निगरानी इकाई ने रिश्वत लेते और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिन लोक सेवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, केवल उनकी सूचना वर्ष वार दी गई है। जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में अवधेश कुमार सिंह, देवेंद्र प्रसाद, आरबी चौधरी, शार देनु भूषण ,वरुण शिव दार, एआर मिश्रा, बीसीपी सिंह,केपीसी, दिगंबर प्रसाद तिवारी ,रवि कांत तिवारी, अवधेश कुमार ओझा, प्रियदर्शनी, बैजनाथ, अकबर हुसैन, दीपक, अरुण विवेक कुमार, संजय कुमार सिंह, अनुभूति श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र प्रसाद, ज्योति मृत्युंजय कुमार, अविनाश प्रकाश ,मनोरंजन अखिलेश्वर प्रसाद, अरुण कुमार सिंह ,नवीन कुमार, रूपक कुमार, सुरेश चौधरी ,अभिषेक सिंह, शैलेंद्र कुमार भारती राजीव रंजन और अनिल कुमार, यादव शामिल है जबकि रिश्वत लेने के मामले में विजय कुमार अरुण कुमार भी शामिल है। ●

विश्व कैंसर दिवस का आयोजन

होम्योपैथिक में है प्रतिरोधक दवा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव पैलेस गोविन्द पुर फतुहा में विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया गया। जिसका अध्यक्षता अनील कुमार शर्मा तथा मुख्य अतिथि डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल, भाजपा नगर अध्यक्ष शोभा देवी,उषा दुबे,राणा राजेन्द्र पासवान। मुख्य अतिथि डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि कैंसर बिहार और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार कैंसर से दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से ज्यादा मौतें होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में दुनिया के 20 फीसदी कैंसर सिर्फ भारत में है। कैंसर के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। भारत में सालाना 8 लाख मौतें होती है। कैंसर 200 से भी अधिक प्रकार का हो सकता है, साथ ही इन सभी के लक्षण भी अलग-अलग होते हैं लेकिन आज हम यहां कैंसर के सिर्फ उन प्रकारों के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमन लाइफ

को तेजी से अपना शिकार बना रहे हैं, आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा फैलने वाले कैंसर के कौन से प्रकार है। ब्लड कैंसर सबसे अधिक पहले वाले कैंसर में ब्लड कैंसर का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। इस बीमारी में इंसान के शरीर की ब्लड सेल्स में कैंसर पनपने लगता है, इसके चलते शरीर में खून की कमी होना और इसका तेजी से पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। स्किन कैंसर के केस भी काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। लंबे समय तक बहुत अधिक तेज धूप में रहने, सही डाइट न लेने और फिजिकल एक्टिविटी न करने जैसे में पनपता है। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर महिलाओं में होता है लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष इस बीमारी का शिकार नहीं होते हैं स्तन कैंसर पुरुषों को भी अपना शिकार बनाता है इस कैंसर के दौड़ान महिलाओं के स्तन में शुरुआती तौर पर एक गांठ जैसी महसूस होती है वह धीरे-धीरे फैलने लगती है और घातक स्थिति में पहुंच जाती है। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर ,बोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि कैंसर का मुख्य कारण आधुनिक खान पान ही है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में कारसोनोसिन 1 एम प्रतिरोधक दवा है। कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से ही इस्तेमाल करें। इस अवसर पर पिंकी कुशवाहा, अनामिका पांडे, शोभा पटेल, ममता पटेल, अंकुश कुमार, आशीष कुमार, पूजा कुमारी, रेखा शर्मा, आशीष कुमार, अमीषा कुमारी ,सीमा कुमारी, सत्येंद्र पासवान बबलू साह, आदि मौजूद थे। ●

घटिया सड़क निर्माण में 11 इंजीनियर नपे, जेल क्यों नहीं!

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अनियमितता वह खराब गुणवत्ता उजागर होने पर विभाग ने जांच के बाद विभाग के सचिव ने 11 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। सड़क निर्माण का मामला औरंगाबाद ,दाउदनगर और मोहनिया कार्य प्रमंडल से जुड़ा है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पदों के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच दिसंबर में की गई थी। जांच में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण एवं उसका अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। सड़कों का निर्माण कार्य समय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो इसके लिए उड़नदस्ता स्टेट क्वालिटी और क्वालिटी से जांच करवाई जा रही है। विभागीय पदाधिकारी द्वारा भी समय पर किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन ,अनुरक्षण पथों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग औरंगाबाद, दाउदनगर और मोहनिया कार्य प्रमंडल के संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। औरंगाबाद कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पर विभागीय कार्रवाई तीन सहायक अभियंता और तीन कनीय अभियंता को निलंबित किया गया है। वहीं दाउदनगर कार्य प्रमंडल के कनीय अभियंता को निलंबित किया गया है। मोहनिया कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जबकि तीन कनीय अभियंता को निलंबित किया गया है वही नवनियुक्त चार सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने सरकार से पूछा है कि तबादला, सस्पेंड और निलंबन कौन सी सजा है कि कुछ दिन के अंदर उसी पद पर पदस्थापित कर दी जाती है। क्या यह जनता को दिग्भ्रमित करना है। ●

पहली बार पांच साल का कार्यकाल योगी ने किया पूरा

● अनील कुमार शर्मा

भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव पैलेस गोविन्द पुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी दूसरी पारी में भी उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास जारी रखे तथा सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नारे को सार्थक करने के लिए दृढ़संकल्प होकर काम किया। योगी सरकार की जनकल्याण की नीतियों और योजनाओं के चलते ही उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई सरकार अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दुबारा सत्ता में आई हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। बेरोजगारी की समस्या हर राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी की चुनौती का योगी सरकार ने बड़े ही अच्छे ढंग से सामना किया। योगी सरकार ने अब बीए, बीएसई और बी कॉम करने वाले युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर देने और एक साल तक सात लाख से ज्यादा बेरोजगारों को 9 हजार रुपए प्रति माह भत्ता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का युवाओं ने स्वागत किया है। अभी तक अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था। इस योजना के तहत स्नातक हुए युवाओं को कम्पनियों और प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप के अवसर देने होंगे। इसका फायदा युवा स्नातकों को होगा। एक तो वह प्रशिक्षण हासिल कर कुशल हो जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें भत्ता मिलेगा। युवाओं को कौशल हासिल करने के बाद नौकरी और रोजगार के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राज्य में ही उन्हें काफी अवसर उपलब्ध होंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की शुरूआत में राज्य के 2 करोड़ श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता देने की नीति के तहत उनके खाते में एक-एक हजार की दो किश्तें ट्रांसफर की थीं। एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ौतरी कर बड़ा तोहफा दिया था। युवाओं को उद्यमी बनाने की राह आसान करते हुए 1.90 लाख उद्यमियों को 16 हजार करोड़ के ऋण वितरित किए गए।

भाजपा सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन में 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। राष्ट्रीय स्तर की एजैंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 2017 से पहले भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। भर्तियों में जमकर वसूली की जाती है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया और भर्ती की हर प्रक्रिया को मिशन रोजगार के तहत बढ़ाया। भर्तियों में भाई-भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाकर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकार ने नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। गौरक्षा पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से मजबूत किया है उसे देखकर अर्थशास्त्री भी हैरत में हैं। योगी सरकार भाजपा की रीति-नीति के अनुसार हिन्दुत्व की छवि को प्रतिष्ठित कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण इसके उदाहरण हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। सरकार नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने पर विशेष बल दे रही है। गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना पर कार्य चल रहा है। योगी सरकार ने राज्य में पर्यटन विशेषकर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। राज्य में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में बेघरों को आवास देने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना प्रारम्भ की गई। निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारम्भ किया गया। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है और कारोबारियों का अनुमान भी बेहद उत्साहवर्धक है। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शोभा देवी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, भाजपा मीडिया प्रभारी शोभा कुमारी पटेल, अनामिका पाण्डेय, रेखा शर्मा, अंकुश कुमार, आशीष कुमार, अमीषा कुमारी, सीमा कुमारी, ममता पटेल आदि मौजूद थे। ●

आश्चर्य परंतु सत्य

बारिश होते ही खुद चलने लगेंगे 8 संप हाउस

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बारिश होते ही खुद चलने लगेंगे 8 संप हाउस ? यह सुनते ही लोग आश्चर्य चकित हो जाएंगे, परंतु सत्य है। पटना के गंगा किनारे शहरों के बीच हुई द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना प्रतियोगिता में पटना नगर निगम की योजना चयनित कर ली गई है। प्रतियोगिता के आधार पर गंगा किनारे के 20 नगर निकायों का चयन किया गया ,जिसमें पटना नगर निगम भी शामिल है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के तहत नगामि गंगे परियोजना के नगर निगम की योजना की मंजूरी देते हुए 11.49 करोड़ की राशि की स्वीकृति भी दे दी गई है। गंगा किनारे के 20 शहरों के चयन में पिछले वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में सुधरे रैंकिंग को भी आधार बनाया गया है। पटना नगर निगम की योजना का चयन होना बड़ी बात है। निगम में अपनी योजना के तहत 8 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत पटना स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से 8 संप हाउस को भी जोड़ा जाएगा। स्काडा सॉफ्टवेयर के माध्यम से संप हाउस कि रियल टाइम निगरानी की जाएगी। नगर आयुक्त के निर्देश पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। मई से पहले स्वचालित हो जाएंगे पंपिंग स्टेशन। मई के पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है आने वाले मानसून से पहले प्रमुख ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। इन पंपिंग स्टेशनों में आईओटी डिवाइस लगाए जाएंगे। इस यंत्र के लगाने से बारिश होते ही सभी पंप हाउस चलने लगेंगे। निकासी होने के बाद यह बंद भी हो जाएगा। कमांड सेंटर से सभी प्रभावों की निगरानी भी होगी ,अभी तक कई बार समय से कर्मी द्वारा संभव नहीं चलाए जाने से जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जाते थे। कमांड सेंटर से पता चल जाएगा कि कौन सा संप हाउस नहीं चल पाया है और किस जगह का चला है। इसे चालू हो जाने से पटना शहर में जल जमाव का संकट समाप्त हो जाने की उम्मीद है। ●

श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान शिव के जन्म की कथा

● रीता सिंह

भगवान शिव के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे तब एक जलते हुए खंभे से जिसका कोई भी ओर-छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए और भगवान शिव प्रकट हुए।

विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। यह कहानी बेहद मनभावन है। जिसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम 'ब्रह्मा' नहीं है इसलिए वह रो रहा है, तब ब्रह्मा ने शिव का नाम 'रूद्र' रखा जिसका अर्थ होता है 'रोने वाला'। शिव तब भी चुप नहीं हुए। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे

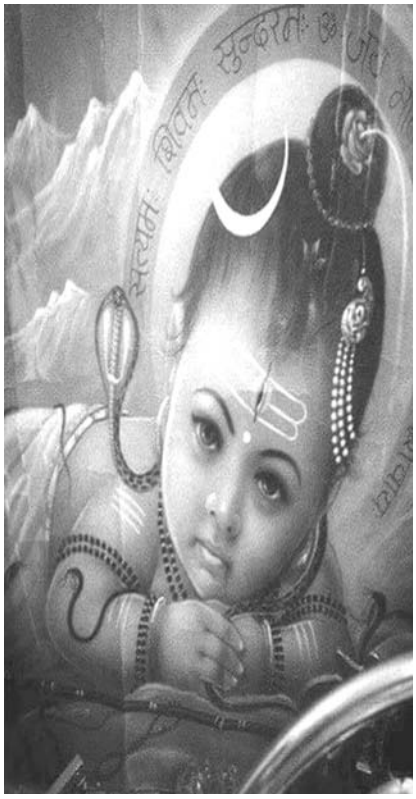

फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों (रूद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव) से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्माण्ड जलमग्न था तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा-विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई।

ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु-कैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। ●

यूपीएससी मेहनत के साथ-साथ अनुशासन भी मांगता है : शैलजा पाण्डेय

आईएएस की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर प्रतिभागी की यह सपने,चाहत एवं उम्मीद की पंख को नई उड़ान देता हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में हर साल लाखों अभ्यर्थी अपने सपने संजोए भाग लेते है लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो जोश जुनून,आत्मविश्वास से भरपूर और विकट परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जिनकी संख्या प्वाइंटो में रहती है। यूपीएससी द्वारा संचालित इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का अतीत भले ही शानदार न रहा हो लेकिन कर्मठता ,दक्षता और अनुभव भविष्य को सुनहले अक्षरों में अंकित कर देते हैं। हर साल सफल अभ्यर्थियों में अधिकांश की कहानी गरीबी और समस्याओं के मिश्रण पर टिकी मिलती हैं लेकिन उनकी पैनी नजर बाज की तरह लक्ष्य पर केंद्रित होने की वजह से वह सफलता की सीढ़ियों को पार कर चुके होते हैं। आज हम ऐसे ही एक सफल अभ्यर्थी की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम लगन के दम पर यूपीएससी की दहलीज को दो दो बार पार कर चुकी हैं। वह शख्सियत हैं उत्तराखंड के नैनीताल की मूल निवासी बिहार कैडर की 2021 बैच की आईएएस शैलजा पांडेय का। पत्रिका के विशेष प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** ने ट्रेनी आईएएस **शैलजा पाण्डेय** से खास मुलाकात की जिसके संपादित कुछ अंश:-

2021 बैच की आईएएस शैलजा राजधानी पटना अंतर्गत धनरूआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य संभाल अपने आईएएस की ट्रेनिग को पूरा कर रही है। उतराखंड के नैनीताल से ताल्लुक रखने वाली शैलजा ने बातचीत के क्रम में बताया कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जहां उनके पिता जी दीप चंद्र पाण्डेय पेशे से इंजीनियर हैं वहीं माता जी डॉ शोभा पांडेय पेशे से डॉक्टर हैं जबकि छोटा भाई यथार्थ पाण्डेय पॉवर ग्रिड में इंजीनियर हैं। घर में शिक्षा का माहौल शुरू से ही रहा हैं और इस माहौल के साथ शैलजा बचपन से ही शिक्षा के प्रति काफी जागरूक रही है और उन्होंने सेंटमरी कॉन्वेंट स्कूल से दसवीं और बारहवीं की परीक्षा पास की और हमेशा की तरह टॉपर रही। उसके बाद उच्च शिक्षा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एन आई टी हमीरपुर हिमाचलप्रदेश से किया । इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर और अपने प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी की दहलीज पर दस्तक देते हुए ऑल इंडिया अकाउंट सर्विस के लिए चयनित हुई लेकिन मन में आईएएस की ख्वाब पाली हुई शैलजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखा और यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 61वे रैंक के साथ आईएएस के लिए चयनित हो गई। अपने संघर्ष के दिनों को याद कर आईएएस शैलजा बताती हैं कि नौकरी के साथ साथ यूपीएससी के लिए तैयारी करना तो कठिन हैं लेकिन उतना भी नहीं की जिससे सफल न हो सके। इसके कई उदाहरण मिल सकते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी के दरम्यान तैयारी जारी रखा और अंतत: सफलता पाई जिसमे से मैं भी एक हूं। परीक्षा की तैयारी काफी अनुशासित ढंग से मैने किया हैं,रिवीजन पर फोकस करने के साथ साथ नोट्स की तैयारी और टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी रहता है। इसके अलावे सफल लोगो का, बैचमेट का मार्गदर्शन का भी काफी लाभ मिला।

बतौर आईएएस बिहार कैडर काफी अच्छा जगह हैं। राजधानी पटना से सटे धनरूआ में काफी चीजे समझ देख रही हूं। यहां हर तरह की चुनौतियों को देखना, जिला प्रशासन के साथ मिलकर त्वरित समस्याओं पर निष्पादन के साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहां कार्य करने के लिए काफी स्कोप हैं। लाबासना की थेरोटिकल ट्रेनिग से भी फील्ड में कार्य करने में काफी आसानी मिलती है क्योंकि वहां मानसिक रूप से आपको काफी मजबूत बना दिया जाता है ताकि स्वयं निर्णय लेने में देर न हो। यहां टीम वर्क के रूप में कार्य करते हुए काफी कुछ देख रही हूं। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के बारे में बताया की सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए की आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? इस परीक्षा में शॉट कट नहीं हैं यूपीएससी मेहनत के साथ-साथ अनुशासन भी मांगता हैं। इसके लिए सिलेबस की सही जानकारी और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उचित मार्गदर्शन काफी महत्वपूर्ण होता हैं।अपने लक्ष्य को केंद्रित कर तैयारी में जुटे रहने पर सफल होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। केवल सच पत्रिका के माध्यम से पटना वासियों को संदेश देते हुए बताया कि जिला प्रशासन आपलोगो की सेवा के लिए ही हैं और प्रशासन हर संभव हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहती हैं। हमलोग आज पटना में सेवा दे रहे है कल किसी दूसरे शहर की सेवा में लग जाएंगे ये शहर आपका हैं, इसे स्वच्छ सुंदर बनाने में अपनी महत्ती भूमिका को निभाए। ●

अतिपिछड़ों की चट्टानी एकता से 2024 में लाल किले पर फहरेगा तिरंगा

● अमित कुमार सिंह/अनिता सिंह

पाटलीपुत्र की पावन धरती एतिहासिक बापू सभागार में जन नायक कपूरी ठाकुर की 99वी जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह का द्वीप प्रज्जवलित कर विधिवत शुरूआत किया गया। जदयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस जयंती समारोह में सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैलचित्र पर पुष्पांजली अर्पित कर उन्हे नमन किया गया। आयोजको ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह भेट कर मखाना एवं फूलो की बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा पूर्व से ही हमलोग जन नायक कपूरी जी की जयंत्री के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करते रहे है। वर्ष 1988 में 64 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई जिससे हमें काफी दुख हुआ। हम उस समय विधायक थे वे हमे बहुत मानते थे। बिहार के विकास के लिए हर तरह से हर क्षेत्र मे काम किया। सीएम ने कहा कि जो पार्टी थी उसी मे लोग इधर उधर चले गये। उसके बाद भी काम करते रहे वो चले गये अगर वो रहते तो वो ही नेतृत्व करते हमलोग जन नायक की स्मृति में उनके काम की चर्चा करते रहते है। उनकी कार्यो को गिनाया। जहाँ उनका आवास था जहा वे रहते थे उसे भी बनाया गया है। हमने उसी समय हमने संकल्प लिया कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर काय्रक्रम का आयोजन करते रहेगें। वर्ष 1989 में यह कार्यक्रम शुरू किया गयां कार्यक्रम मे बड़ी संख्या में लोग वढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है। जिसको ध्यान मे रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को बापू सभागार में 5000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस अवसर पर जननायक को याद करने के लिए काफी संख्या में बापू सभागार के बाहर लोग मौजुद थे। यह देखकर मुझे काफी खुशी हुई की हमलोगो के जन नायक की स्मृति के अवसर पर उनके द्वारा किये गये विकास कार्यो और उनकी बातों को लोगों के बीच प्रचारित करना शुरू किया। 2020 के कोरोना के कारण दो साल कार्यक्रम स्थगित था। हालाकी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम होता था। हर वर्ग का उत्थान का नाम किये जा रहे है। हम जननायक कपूरी जी को नमन करते है। जब तक जीवित रहेगें लोक हित में काम करते रहेगें।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 'संविधान बचाओं देश बचाओं' का संकलप लेते हुये कहा कि जन नायक कपूरी ठाकूर जीवन पर्यतन गरीबों, किसानों, मजदुरों एवं बंचित समाज के बड़ी समुहो के लिए संघर्षरत है। ललन सिंह जदयु राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भाजपा आरक्षण विरोधी है। चार पंचायत चुनाव 2021 तक हो चुके है। 2022 में नगर निकाय चुनाव भाजपा के इस आरक्षण को समाप्त करने की साजिस की नीतीश कुमार ने कहा कि बिना आरक्षण हम चुनाव नही होने देगें। अधिसूचना हो गई तब भी चुनाव रोकने का उपक्रम किया। आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार अतिपिछड़ा विरोधी है। सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कसौटी पर तौला जाय तो कपूरी जी जैसा कोई नेता नहीं नीति और नेतृत्व की बात करे तो नीतीश कुमार जैसा कोई नही वे जन नायक के कार्यो को आगे बढ़ा रहे है। सूचना जन सम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि 2005 जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने मुख्य मंत्री के बंगले में शिफ्ट करने से पहले ही उन्होंने अति पिछड़ों तथा महिलाओं को आराक्षण दिया। यह पंचायत चुनाव से इस समाज से हजारों नेतृत्व पैदा हुये। अतिपिछड़ा समाज ताकत देता है। तो लाल किले पर झंडा फहराने से कोई रोक नही सकता है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा अतिपिछड़ा समाज को सशक्त बनाया इसलिए नीतीश कुमार के साथ खड़ा मंत्री विजय चौधरी ने कहा बिहार की ऐसी कोई पार्टी नही जिसका काम बिना जननायक के चले, पर उनके सिद्धान्त पर चलने वाली असली पार्टी है। अति पिछड़ा समाज मिला तो हमारे नेता को आगे बढ़ने से कोई नही रोक सकता है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा अति पिछड़ा समाज ठानले तो लाल किले पर झण्डा फहराने से कोई नही रोक सकता। सांसद तथा कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने अतिपिछड़ा समाज ने नेताओं व कार्यकर्ता से अपील की है कि 2024 के महाभारत में नीतीश कुमार को आगे बढ़ाये।

जहानाबाद सांसद चन्देखर चन्द्रवंशी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पंचायत में 20 आरक्षण देकर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। महिलाओं का आरक्षण देकर महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। आज मै सांसद हूँ तो ये देन भी विकास पुरूष नीतीश कुमार की देन है। अतिपिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य दो बार ओबरा विधान सभा पूर्व प्रत्याथी प्रमोद चन्द्रबंशी ने कपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मॉग रखी कहा कि गरीबों के जनजन के मसीहा जननायक को केन्द्र सरकार भारत रत्न नही दे रही है। केन्द्र सरकार का रवैया अतिपिछड़ा विरोधी है। कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा जिसमें औरगांबाद से सैकड़ों की

संख्या में कार्य कर्ता ने भाग लिया। सीएम नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर का मानस पुत्र बताया। सीएम उनके आदर्शो पर चल रहे है। अतिपिछड़ा वर्ग के मसीहा है। रोहणी कमीशन की रिर्पोट शीघ्र लागु करने की मॉग उठाई 2024 में लोक सभा में सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने का संकल्प कार्यकत्ता लेकर जाय ताकि हमारे नेता 2024 में प्रधानमंत्री बन सके। हमलोग फर्जी राष्ट्रवाद और हिन्दुवाद से सर्तक और सावधान रहना है। उन्होनें अतिपिछड़ा को पंचायती राज के आरक्षण देकर राजनैतिक अधिकार दिया। तथा लोक सभा एंव विधान सभा में अतिपिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मॉग किया। उन्होनें कहा कि नीतीश कुमार राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया आज बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। अति पिछड़ा समाज की पहचान देश स्तर पर हो तो नीतीश कुमार जी साथ मजबुती के साथ खड़ा रहना होगा। आज अतिपिछड़ा समाज चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह निषाद व संचालन महासचिव धमेन्द्र चन्द्रवंशी ने किया। मौके पर विजेन्द्र प्रसाद यादव, जितेन्द्र कुमार राय, लैसी सिंह, शीला कुमारी, सांसद फैयाज आरलम, विधान परिषद संजय कुमार सिंह उर्फ गॉधी , कुमुद वर्मा पूर्वमंत्री अब्दुल वारी सिद्धिकी, कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा मौजुद थे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हम सुप्रिमों जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर गरीबों के हित में मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने की मॉग की थी उन्होनें कहा कि बिना अंग्रेजी मैट्रिक परीक्षा लेने का

कपूरी मॉडल लागु किया जाय। अपने आवास 12 एम. स्टैड रोड पर आयोंजित समारोह में उन्होनें तैलचित्र पर मैट्रिक में प्रथम श्रेणी अंक लाकर भी अंग्रजी में फेल कर जाते है। इसलिए अंग्रेजी की मान्यता हटाकर कर्पूरी मॉडल किया जाये। यह कर्पूरी जी की सच्ची श्रद्धांजली होगी। गरीबो के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग दुहराते हुए कहा कि झुगी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने से पहले उनके पुनर्वास भी व्यवस्था की जाये। इधर वी०आई०पी० प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि कपूरी ठाकुर का जन्म साधारण परिवार मे हुआ था। राजनीति मे लम्बा सफर बिताने के बाद भी जब उनका निधन हुआ तो उनके परिवार को विरासत मे देने के लिए एक मकान तक उनके पास नही थे। अपने जीवन काल मे समाज और गरीबो दलितो शोसितो के हित में कार्य करते रहे। उन्होने बिहार सरकार से अन्य राज्यो की तरह अतिपिछड़ो की आवादी के अनुकुल आरक्षण का लाभ देने की मांग की। साथ जितनी उनती राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की।●

रंगों का त्योहार होली के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज विलासपुर, भगवानपुर हाट (सीवान) के समस्त जनता-जर्नादन को हार्दिक शुभकामनाएँ।

-: निवेदक :-

मालती देवी

मुखिया, ग्राम पंचायत राज
विलासपुर, भगवानपुर हाट (सीवान)
मो०:- 9708121636

अमितेश कुमार

मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज
विलासपुर, भगवानपुर हाट (सीवान)
मो०:- 9708121636

चीन भारत में दखलअंदाजी कर रहा है, इस पर रोक लगे : कौशलेन्द्र

● मिथिलेश कुमार/ललन कुमार

लोकसभा में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में भाग लेते हुए जोरदार तरीका से देश की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि आज देश में सरकार अमृतकाल के 25 वर्ष का कालखण्ड मना रही है। परन्तु देश की जनता को अमृतकाल का जो अनुभव होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। सपने तो दिखाये गये और लगातार दिखाये जा रहे है, परन्तु देश की जनता को इसका क्या लाभ मिल रहा है? प्रधानमंत्री जी ने वायादा किया कि सभी के खाते में 15-15 लाख देंगे, हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट-सिटी और आदर्श ग्राम आदि सभी वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाने के कारण इस्तीफा दे दिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी भी विचार करेंगे? सरकारें 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है, किन्तु सपने 25 वर्षों के दिखाये जाते हैं।

☞ 2047 तक राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, किन्तु देश में कई राज्य विकास की दौर में पिछड़े हुए हैं। बिहार अंतिम पायदान पर है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाये बिना देश के समावेशी विकास का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है। इसीलिए हमारे नेता एवं मा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आग्रह है कि बिहार को अन्य राज्यों को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा के समान ही बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। जिससे कि वहाँ भी विकास की रूपरेखा तैयार हो।

☞ ऐसा भारत जिसमें गरीबी न हो-फिर भी आज देश में करीब 80 करोड़ लोगों को मात्र 5 किग्रा. मुफ्त अनाज देने पर सरकार अगले एक वर्ष तक बढ़ाने की बात करती है। उनको आत्मनिर्भर कब तक बनाया जायेगा।

☞ करीब 90 प्रतिशत लोगों की मासिक आय 10 हजार रू. से भी कम है। मेरी मांग है कि सरकार इस दिशा में कोई सार्थक कदम उठाये।

☞ ऐसा भारत जिसकी युवा शक्ति, नारी शक्ति और समाज एवं राष्ट्र की बात की जा रही है। युवा शक्ति बेरोजगार है। जनवरी, 2023 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत है। रोजगार सृजन के उपाय होने चाहिए, जबकि रोजगार को ही समाप्त किया जा रहा है।

☞ आरक्षण से बचने के लिए आऊट-सोर्सिंग से काम लिया जा रहा है। यह कदम बेरोजगार युवाओं के बहुत बड़े वर्ग के लिए आत्मघाती हो रहा है।

☞ नारी शक्ति की बात की जा रही है। उस नारी शक्ति को सम्मान महिला आरक्षण को लागू करके ही किया जा सकता है।

☞ एक तरफ समाज और राष्ट्र की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज को बाँटने का काम हो रहा है। धर्म के नाम पर समाज में जहर घोला जा रहा है। सबका साथ-सबका विकास-न्याय के साथ ही सम्भव होगा।

☞ बड़े-बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार की बात हो रही है और अभी एक सप्ताह से देश-दुनियां के दूसरे नम्बर के धनी व्यक्ति को नीचे जाते देखा जा रहा है। उन्होंने तो देश की साख पर ही बट्टा लगा दिया है। कहाँ हैं-सेबी, आरबीआई, बैंक और ईडी सभी सरकार की संस्थायें। क्या उन्हें यह नेक्सस नजर नहीं आ रहा है? सब खामोश हैं। जो किसी भी विषय पर बोलने को आगे रहते हैं, सब के सब खामोश हैं। क्या इसकी स्वतंत्र जाँच होगी? नियामक के दोषियों की जिम्मेवारी तय होगी की नहीं।

☞ दुनियां की 5वीं अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है।

☞ महोदय, जिस जीडीपी को सरकार के सांसद मानने को तैयार नहीं थे, वही आज जीडीपी के आधार पर दुनियां की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोड मैप देश की जनता के सामने होना चाहिए। आज तो आप मात्र एक ही बड़े उद्योगपति का खुलासा होने पर 5वीं अर्थव्यवस्था से नीचे खिसक गये।

☞ मंहगाई-महोदय, मंहगाई चरम पर है। आम जनता मंहगाई से त्रस्त है। सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार को बफर स्टाक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा करनी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव के अनुपातित नहीं है। सरकार और तेल कम्पनियां मुनाफा कमा रही है। जनता मंहगाई का बोझ झेल रही है। इसे जीएसटी के दायरे में लाना ही एक मात्र उपाय है।

☞ डॉलर के मुकाबले रूपया गिरता जा रहा है। विदेशी व्यापार घाटा बढ़ रहा है। देश आर्थिक मंदी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन काम नजर नहीं आ रहा है।

☞ किसान और कृषि उत्पादन-किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा सरकार कर रखी है, जिसे वर्ष, 2022 के दिसम्बर माह का लक्ष्य रखा गया था, क्या हुआ। किसान आज भी अपने अधिकार के लिए आन्दोलन करने के लिए मजबूर है। एमएसपी को कानूनी गारण्टी नहीं दिया गया है। कृषि उत्पादन तो मौसम पर निर्भर है। पिछले वर्ष मौसम थोड़ा गरम हुआ, गेहूँ का उत्पादन कम हो गया और मंहगाई चरम पर आ गई। बिचौलिए खूब कमाई करने में लगे हैं। क्योंकि स्टाक तो उनके पास है।

☞ आज बिहार में आलू 5 रूपये किलो किसान बेचने के लिए मजबूर है। वहीं एक महीना बाद जब किसान से कारोबारियों के गोदाम में जायेगा-फिर वही आलू 20 से 25 रूपये किलो में बिकने लगेगा। बिचौलियों पर कोई अंकुश नहीं है। इसी प्रकार इस वर्ष बिहार एवं अन्य कई राज्यों में यूरिया खाद की किल्लत कर दिया गया। किसान ब्लैक मार्केट से दोगुने दाम पर खरीदने के लिए मजबूर हो गये। यह परिस्थिति किसानों के लिए उत्पन्न कर दिया जाता है।

☞ पड़ोसी देशों के साथ संबंध-चीन की वजह से हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध मधुर नहीं है। चीन सभी देशों में अपना दखलअंदाजी कर रहा है। अपना प्रभुत्व जमा रहा है। सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है। चीन हमारी सीमा पर भी अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। यह देश के लिए चुनौती का विषय है। सरकार चीन से कैसा संबंध चाहती है। क्योंकि एक तरफ चीन आक्रामक है, दूसरी ओर हमारा व्यापार भी चल रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। अतः चीन पर निर्भरता कम करने के उपाय होने चाहिए, नहीं तो शान्ति स्थापित करना मुश्किल हो जायेगा।●

समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे नवादा

जीविका के द्वारा चलाये जा रहे कार्यों को सराहा

● **मिथिलेश कुमार**

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के क्रम में नवादा जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नवादा जिलान्तर्गत नवादा प्रखंड की भगवानपुर पंचायत में कबीरपुर ग्राम का भ्रमण कर विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। उद्यान निदेशालय द्वारा भगवानपुर ग्राम में लगाई गई प्रदर्शनी, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत आलू और गेहूं की हो रही खेती का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिला बागवनी विकास समिति नवादा, जिला उद्यान कार्यालय नवादा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में जैविक तरीके से उत्पादित मशरूम, पान, केला, पपीता आदि का अवलोकन किया और उत्पादकों से बातचीत की। पॉली हाऊस में हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के द्वारा लेट्स / बेसिल की खेती जैविक तरीके से उत्पादित टमाटर, अमरूद, मूली, बैगन आदि के संबंध में मुख्यमंत्री ने उत्पादकों से जानकारी ली। सामुदायिक भवन कबीरपुर में बिहार महादलित विकास मिशन के तहत संचालित भारती किशोर समूह की बालिकाओं से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कबीरपुर ग्राम के भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना, जल - जीवन - हरियाली अभियान के तहत जीर्णोद्धार किये गये कुएं, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली योजना का जायजा लिया। सतत् जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी जीविका दीदियों द्वारा खोले गए राशन / श्रृंगार की दुकान एवं किए जा रहे गौपालन एवं मुर्गीपालन का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक को मुख्यमंत्री ने मौके पर चेक प्रदान किया। उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आदि

के संबंध में दिए गए लाभ के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जीविका समूहों की दीदियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत 545 लाभान्वित परिवारों हेतु 1 करोड़ 91 लाख रुपये का चेक एवं जीविका दीदियों को सतत् जीविकोपार्जन योजना का किट मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने चेक प्रदान किया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों एवं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित छात्रों को उन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्राथमिक विद्यालय, कबीरपुर में सात निश्चय योजना-2 के तहत महादलित, दलित, में अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत संचालित साक्षर सखी अभियान का उन्होंने निरीक्षण किया। बुनियादी साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके दीदियों को मुख्यमंत्री ने प्रमाण-पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत भगवानपुर सरकार भवन के समीप समेकित मत्स्य-सह-बत्तख पालन का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। पुस्तकालय एवं कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का भी उन्होंने मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि अनुदानित दर पर किसानों को दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के संबंध में अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। धान कुट्टी मशीन को लेकर लोगों को जागरूक करें। इसके द्वारा कुटाई किए गए चावल की गुणवत्ता काफी

बेहतर होती है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग सभी जिलों में जाकर एक-एक चीज को देख रहे हैं। यह देखना जरुरी है कि कहां पर कितना काम हुआ है। गरीब-ब-गुरबा तबके के लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है उससे वे लोग और आगे बढ़ेंगे। कहीं जाने पर अगर यह पता चलता है कि यहां पर काम नहीं हो रहा है तो उसी समय हम जिलाधिकारी को इसे देखने के लिए कह देते हैं। यहां के साथ-साथ बाकी जगहों पर भी काम होना चाहिए। लोगों की बात सुनने से सभी बातों की जानकारी मिल जाती है। इस बार वर्षापात कम होने से बिहार के 9 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुये थे। इन इलाकों का हमने एरियल सर्वे किया था और कुछ जगहों पर जाकर हमने देखा भी था। कम वर्षापात के कारण जो किसान खेती नहीं कर पाये थे, उनको जो मदद देनी थी, हमलोगों ने दे दी है। इसके अलावा जो भी उपज हुयी है, उसका प्रोक्योरमेंट का काम भी चल रहा है। आगे और क्या किया जाना है उसको भी देखा जा रहा है। नवादा में गंगाजल पहुंचाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द गंगाजल नवादा के हर घर तक पहुंच जायेगा। इसी साल कुछ ही महीनों में उसे पूरा कर लिया जाएगा। हमने सुझाव दिया है कि गंगाजल को किस रास्ते से ले जाया जाए। गंगाजल पहुंचाने को लेकर काम तेजी से जारी है। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, बुधौल (नवादा) का निरीक्षण किया। छात्रावास प्रांगण में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात सामाजिक पापों को अंकित करायें। छात्रावास निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, जननायक पुस्तकालय सह डिजिटल अध्ययन केंद्र का मुआयना कर उन्होंने छात्रों से बातचीत की और कमियों को दूर करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें

नमन किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में दीदी की रसोई का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और इसका निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दीदी की रसोई को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में संचालित किया जाना है, इसे जल्द से जल्द सभी जगह लागू करायें।

निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने काफी पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की शुरुआत करायी थी। हमने कई जगहों पर बहुत पहले ही इसको शुरु करा दिया था। किसी कारण से दो-तीन जगहों पर इसका निर्माण नहीं हो पाया था। इसे लेकर हम हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। यहां का छात्रावास बनकर पहले से तैयार है। यहां पर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। यहां पर एक-एक चीज को पढ़ाया और बताया जा रहा है। गरीब-गुरबा तबके के छात्र-छात्राओं के लिए यह सब इंतजाम कराया गया है। नवादा में पटना की तरह अच्छे पार्क के निर्माण की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्क का निर्माण भी यहां कराया जायेगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं एवं जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने जगह-जगह मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

समाधान यात्रा में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा, उद्योग मंत्री सह नवादा जिले के प्रभारी मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह, विधायक मो० कामरान, विधायक श्रीमती नीतू कुमारी, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, सचिव अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण श्री दिवेश सेहरा, कृषि सचिव श्री एन0 सरवन कुमार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका सह मिशन निदेशक जल - जीवन - हरियाली अभियान श्री राहुल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री संजय सिंह, आयुक्त मगध प्रमंडल श्री मयंक बरबड़े, पुलिस महानिरीक्षक मगध प्रक्षेत्र श्री क्षत्रनील सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार, जिलाधिकारी नवादा श्रीमती उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक नवादा श्री अंबरीष राहुल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ●

उग्रवादी संगठन करा रहे अफीम की खेती

सरकारी नलों से हो रही सिंचाई, वन विभाग अनजान

● **मनीष कमलिया/कृष्ण कुमार चंचल**

जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रखंड क्षेत्र के पिपरा परतौनिया के घने जंगलों के बीच वन विभाग की कई एकड़ भूमि पर माफिया और उग्रवादी संगठन अफीम की खेती कर रहे हैं। और तो और सरकारी नल-जल योजना के तहत लगाई गई पानी टंकी से सिंचाई भी की जा रही है, बावजूद वन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। सूत्रों का मानना है कि रजौली थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित हरदिया पंचायत की डैम के उस पार पिपरा परतौनिया के घने जंगलों के बीच वन विभाग की कई एकड़ भूमि पर अभी भी अफीम का पौधा लहलहा रहा है। अफीम की खेती के लिए माफिया और उग्रवादी संगठन जंगल में लगे हरे भरे पेड़ों को काटकर बर्बाद कर उस जगह पर अफीम की खेती कर रहे हैं। घने जंगल में लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए सरकार ने नल-जल योजना के तहत पानी टंकी लगाया है। उसी टंकी में लगे मोटर से अफीम के खेतों में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचा कर सिंचाई किया जा रहा है। ऐसे तो वन विभाग के अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं लेकिन, उन्हें अफीम का पौधा उनके भूमि पर लगे होने की भनक कैसे नहीं लग पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जंगली क्षेत्रों में अफीम खेती को संरक्षण देने का काम उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और भाकपा माओवादी के स्लीपर सेल के सदस्य इस काम को बड़े सफाई तरीके से करते हैं। जंगल में निवास कर रहे गरीब तबके के लोगों को धमका कर बहला-फुसला कर धन का लोभ देकर अफीम के खेती में उन लोगों को सम्मिलित करते हैं। उग्रवादी संगठन अफीम की खेती से अर्जित करोड़ों रुपए से अपने संगठन को मजबूत करते हैं। पिछले कई वर्षों से रजौली, सिरदला, कौआकोल वह गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों की चहल कदमी पर पूरी तरह से विराम लगा हुआ है। इसका कारण यह है कि पुलिस पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नजर रख रही है और नक्सलियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही है। बावजूद क्षेत्र के दर्जनों ऐसे लोग हैं, जो नक्सली संगठन के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। ऐसे तो इस बार पुलिस ने उग्रवादी संगठन को बड़ा नुकसान दिया है। अफीम के दो एकड़ फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद नक्सलियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बावजूद अभी भी जंगल में कई एकड़ में अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं।

☞ **पुलिस टीम पर हुआ है हमला :-** बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं है कि रजौली थाना क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है। साल 2008 में हरदिया पंचायत की पिछली, जमुंदाहा गांव के पास अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हुई थी। जिसे पुलिस नष्ट करने गई तो पुलिस बल पर उग्रवादी संगठन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फायरिंग किया था। हाल के ही कुछ साल पहले एसएसबी के जवानों ने नामजद प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साल 2022 में परतौनिया गांव के पास उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में अफीम की खेती नष्ट की गई थी। नए साल 2023 में 4 फरवरी को पुलिस ने परतौनिया गांव के पास ही अफीम की खेती को नष्ट किया है। बावजूद अब भी अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं।●